Kamal.Sandesh kamalsandesh.org KamalSandesh

कमल संदेश

वर्ष-20, अंक-04 16-28 फरवरी, 2025 (पाक्षिक) ₹20

'भाजपा की सरकार दिल्ली में भी विकास करके दिखाएगी'

दिल्ली विधानसभा चुनाव परिणाम-2025

भाजपा की ऐतिहासिक जीत
आप-दा की करारी हार

> यह बजट बचत को बढ़ाएगा, निवेश को बढ़ाएगा, खपत को बढ़ाएगा और विकास को भी तेज़ी से बढ़ाएगा।
>
> – श्री नरेन्द्र मोदी
> प्रधानमंत्री

केंद्रीय बजट

2025-26

UNION BUDGET

2025-26

"डेमोक्रेसी, डेमोग्राफी और डिमांड विकसित भारत यात्रा के प्रमुख स्तंभ हैं।"

– श्रीमती निर्मला सीतारमण

'विकसित भारत' के व्यापक सिद्धांत

- गरीबी से मुक्ति
- आर्थिक गतिविधियों में 70 प्रतिशत महिलाएं
- 'फूड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड' बनना
- शत-प्रतिशत अच्छे स्तर की स्कूली शिक्षा
- शत-प्रतिशत कुशल कामगार के साथ सार्थक रोजगार
- बेहतरीन, सस्ती और सर्वसुलभ स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच

भाजपा मुख्यालय (नई दिल्ली) में 08 फरवरी, 2025 को आयोजित 'कार्यकर्ता अभिनंदन समारोह' में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी का स्वागत करते भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं केंद्रीय मंत्री श्री जगत प्रकाश नड्डा

भाजपा मुख्यालय (नई दिल्ली) में 08 फरवरी, 2025 को आयोजित 'कार्यकर्ता अभिनंदन समारोह' में कार्यकर्ताओं का अभिवादन स्वीकार करते प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी और भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं केंद्रीय मंत्री श्री जगत प्रकाश नड्डा

भाजपा मुख्यालय (नई दिल्ली) में 08 फरवरी, 2025 को आयोजित 'कार्यकर्ता अभिनंदन समारोह' में कार्यकर्ताओं का अभिवादन स्वीकार करते प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी

भाजपा मुख्यालय (नई दिल्ली) में 08 फरवरी, 2025 को आयोजित 'कार्यकर्ता अभिनंदन समारोह' में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी का स्वागत करते भाजपा राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं दिल्ली प्रदेश भाजपा प्रभारी श्री बैजयंत पांडा, प्रदेश अध्यक्ष श्री वीरेन्द्र सचदेवा तथा पार्टी नेतागण

भाजपा मुख्यालय (नई दिल्ली) में 08 फरवरी, 2025 को दिल्ली विधानसभा चुनावों में भाजपा की ऐतिहासिक जीत के बाद कार्यकर्ताओं के विशाल जनसमूह को संबोधित करते प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी

कमल संदेश

पाक्षिक पत्रिका

संपादक
डॉ. शिव शक्ति नाथ बक्सी

सह संपादक
संजीव कुमार सिन्हा
राम नयन सिंह

कला संपादक
विकास सैनी
भोला राय

डिजिटल मीडिया
राजीव कुमार
विपुल शर्मा

सदस्यता एवं वितरण
सतीश कुमार

इ-मेल
mail.kamalsandesh@gmail.com
mail@kamalsandesh.com
फोन: 011-23381428, फैक्स: 011-23387887
वेबसाइट: www.kamalsandesh.org

विषय-सूची

08 दिल्ली में खिला कमल, 'आप' की करारी हार

दिल्ली विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने कहा था, "आपदा नहीं सहेंगे, बदल के रहेंगे।" दिल्ली की जनता ने भी आप-दा को सहने से इनकार कर दिया। भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली विधानसभा चुनाव में ऐतिहासिक विजय प्राप्त की...

12 दिल्ली में विकास, विजन एवं विश्वास की जीत एवं आप-दा की हार: नरेन्द्र मोदी

कार्यकर्ता अभिनंदन समारोह को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि आज...

14 भाजपा की सरकार दिल्ली में भी विकास करके दिखाएगी: जगत प्रकाश नड्डा

भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने...

18 'लोगों की जेब भरने वाला बजट'

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि आमतौर पर बजट का ध्यान सरकार के खजाने को भरने पर होता है, लेकिन इस बजट में नागरिकों की जेब भरने, उनकी बचत बढ़ाने और उन्हें देश...

32 आदरणीय राष्ट्रपति जी का उद्बोधन 'विकसित भारत' के संकल्प को मजबूती देने वाला है

आदरणीय राष्ट्रपति जी का यह उद्बोधन 'विकसित भारत' के संकल्प को मजबूती...

लेख

सुशासन के सच्चे पथ प्रदर्शक 'भारत रत्न' अटल बिहारी वाजपेयी / **राजकुमार चाहर** 28

अन्य

मिल्कीपुर उपचुनाव में भाजपा की जीत 15

1 लाख रुपए तक प्रति माह की औसत आय पर कोई आयकर नहीं 16

वित्त वर्ष 2026 में वास्तविक जीडीपी में 6.3 फीसदी से 6.8 फीसदी की दर से वृद्धि का अनुमान 24

मोदी स्टोरी 26

कमल पुष्प 26

आज देश बड़े निर्णयों और नीतियों को असाधारण गति से लागू होते देख रहा है: राष्ट्रपति 30

प्रधानमंत्री का राज्य सभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर हुई चर्चा का उत्तर 32

दिल्ली में भाजपा की ऐतिहासिक जीत के बाद पूरे देश में भव्य समारोह 36

प्रकाशक एवं मुद्रक: डॉ. मुकर्जी स्मृति न्यास के लिए विष्णु मित्तल द्वारा मुद्रित एवं प्रकाशित, एच.टी. मीडिया लिमिटेड, प्लॉट नं.-8, उद्योग विहार, ग्रेटर नोएडा (उ.प्र.)-201306 से मुद्रित एवं डॉ. मुकर्जी स्मृति न्यास, पी.पी.-66, सुब्रमण्यम भारती मार्ग, नई दिल्ली-110003 से प्रकाशित। संपादक- डॉ. शिव शक्ति नाथ बक्सी

सोशल मीडिया से

नरेन्द्र मोदी

अटकाने, लटकाने और भटकाने के कांग्रेसी कल्चर से किनारा कर हम देशभर में इंफ्रास्ट्रक्चर के तेज विकास में निरंतर जुटे हुए हैं।

(06 फरवरी, 2025)

जगत प्रकाश नड्डा

हमारी सरकार एंपावरमेंट की बात करती है, हमारी योजनाएं इनके प्रबल उदाहरण हैं, जिन्हें दूसरी पार्टियां कॉपी करती हैं। महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त करने की दृष्टि से भाजपा सरकारों ने उन्हें आर्थिक सहायता देने की योजनाएं शुरू कीं। ये महिला सशक्तीकरण का प्रतीक है। (02 फरवरी, 2025)

अमित शाह

भविष्य में भारत के इतिहास को तीन हिस्सों में बांटा जाएगा- आजादी से पहले और बाद, आपातकाल से पहले और बाद और 'मोदी जी' के आने से पहले का भारत और उनके बाद का भारत।

(31 जनवरी, 2025)

राजनाथ सिंह

मैं वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण को बधाई देता हूं, जिन्होंने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने की दिशा में एक शानदार बजट पेश किया है। यह बजट युवा, गरीब, किसान, नारी के साथ-साथ समाज के सभी वर्गों और क्षेत्रों के विकास को बढ़ावा देने वाला है। खासकर मिडिल क्लास के योगदान का ध्यान रखते हुए यह बजट अभूतपूर्व तोहफा लेकर आया है। बारह लाख रुपये तक की वार्षिक आय पर आयकर से राहत दिए जाने के निर्णय का मैं हृदयतल से स्वागत करता हूं। मैं पुनः प्रधानमंत्री जी को और वित्त मंत्री जी को इस ऐतिहासिक बजट के लिए बधाई देता हूं। (01 फरवरी, 2025)

बी.एल. संतोष

धन्यवाद दिल्ली! आपने उस समय साथ दिया जब इसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। इस जीत के साथ दिल्ली को वैसा संवारने की बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी आयी है, जैसा उसे होना चाहिए। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में दिल्ली भाजपा का हर कार्यकर्ता इसे साकार करने के लिए काम करेगा।

(08 फरवरी, 2025)

निर्मला सीतारमण

दिल्ली के मतदाताओं का भाजपा में अपना विश्वास जताने के लिए धन्यवाद! प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के मार्गदर्शन एवं भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा के नेतृत्व में हम दिल्ली के लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए समर्पित हैं। मैं हर कार्यकर्ता की कड़ी मेहनत एवं समर्पण की सराहना करती हूं।

(08 फरवरी, 2025)

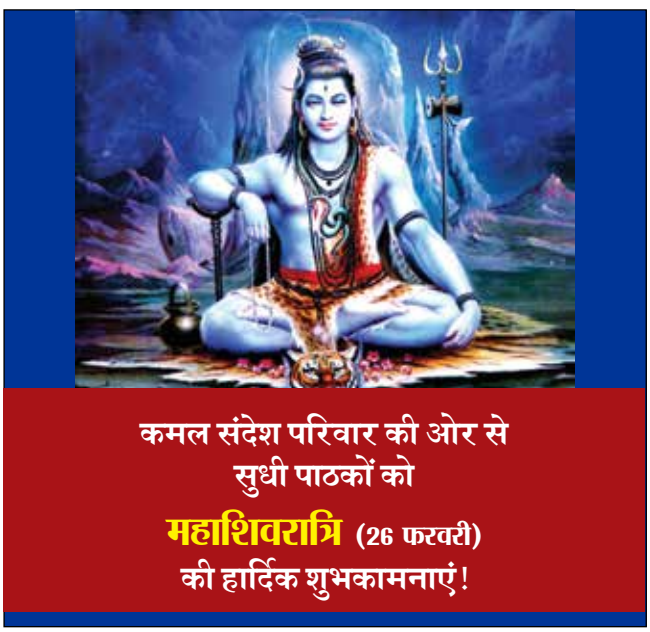

संपादकीय

आशा व विश्वास की नई सुबह

दिल्ली की जनता ने जिस प्रकार से भाजपा पर अपना आशीर्वाद बरसाया, उससे यह प्रमाणित हो गया कि मोदी की गारंटी, 'गारंटी पूरा होने की गारंटी' है। जहां झूठ, फरेब और धोखाधड़ी की राजनीति पराजित हुई, वहीं परफॉर्मेंस, सुशासन एवं विश्वसनीय नेतृत्व विजयी हुआ है। अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में दिल्ली में 'आप' सरकार भ्रष्टाचार, जनता के धन की लूट, जनविश्वास के साथ धोखा, कुशासन एवं छल की राजनीति की प्रतीक बन गई। परिणाम यह हुआ कि 'आप' सरकार दिल्ली के लिए 'आपदा' साबित हुई तथा जनता को मूलभूत सुविधाओं के लिए भी तरसना पड़ा। एक दशक तक जनता इस 'आपदा' को सहने के लिए मजबूर हो गई। सत्ता-केंद्रित, सिद्धांतहीन एवं अवसरवादी राजनीति के पर्याय अरविंद केजरीवाल का असली चेहरा जनता ने पहचान लिया और चुनावों में धूल चटाकर दंडित किया। जहां आप के मतों में 10 प्रतिशत की गिरावट हुई तथा केवल 22 सीटों पर यह सिमट कर रह गई, वहीं भाजपा ने न केवल 70 में से 48 सीटों पर विजय प्राप्त की, बल्कि इसके मतों में एनडीए सहयोगियों के साथ लगभग 9 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई। दिल्ली की जनता, जो पिछले तीन लोकसभा चुनावों से लगातार भाजपा की झोली में सातों सीटें डालती आई है, उसने इस बार भाजपा को विधानसभा चुनावों में भी दो-तिहाई से अधिक बहुमत से आशीर्वाद दिया। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अपील पर दिल्ली की जनता के अपार समर्थन से पूरे देश का वातावरण सकारात्मक एवं उत्साहपूर्ण बन गया है, आशा एवं विश्वास की नई सुबह हुई है।

दिल्ली की जनता, जो पिछले तीन लोकसभा चुनावों से लगातार भाजपा की झोली में सातों सीटें डालती आई है, उसने इस बार भाजपा को विधानसभा चुनावों में भी दो-तिहाई से अधिक बहुमत से आशीर्वाद दिया। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अपील पर दिल्ली की जनता के अपार समर्थन से पूरे देश का वातावरण सकारात्मक एवं उत्साहपूर्ण बन गया है

वर्ष 2025-26 का केंद्रीय बजट कई मायनों में ऐतिहासिक है और इससे क्रांतिकारी परिवर्तन होंगे। कई प्रकार के सुधार एवं समावेशन पर बल के साथ 'विकसित भारत की' रफ्तार बढ़ाने वाला यह बजट मोदी सरकार के मंत्र 'सबका साथ, सबका विकास' को रेखांकित करता है। समाज के हर वर्ग के लिए समर्पित यह बजट समावेशी विकास पर आधारित है। यह बजट चार प्रमुख स्तंभों पर आधारित है- ग्रामीण समृद्धि के लिए कृषि, उद्यमशीलता एवं रोजगार सृजन के लिए एमएसएमई, अवसंरचना के लिए निवेश तथा वैश्विक स्पर्धा एवं आर्थिक विकास के लिए नवाचार एवं निर्यात। बजट का मुख्यतः छह प्रमुख विषयों पर जोर है- कराधान, ऊर्जा क्षेत्र, शहरी विकास, वित्तीय क्षेत्र नियामक सुधार एवं खनन। अनेक राहत देने वाले कदमों के साथ, इस बजट के द्वारा मोदी सरकार ने मध्यम वर्ग के लिए करों में राहत देने का कार्य जारी रखा है तथा वर्तमान के 7 लाख रुपये से बढ़ाकर 12 लाख रुपये तक की आय पर कर 'शून्य' कर दिया है। फलतः एक लाख रुपये तक मासिक आमदनी पर अब कोई कर नहीं लगेगा। इस बजट में समग्रता से छह लक्ष्य दृष्टिगत होते हैं- विकास में तेजी लाना, समावेशी विकास सुनिश्चित करना, भारत के मध्यम वर्ग की क्रय शक्ति को बढ़ाना, निजी क्षेत्र के निवेश को मजबूत करना तथा घरेलू विश्वास को सशक्त करना। 'ज्ञान' (GYAN) के मूलभूत ढांचे के सुदृढ़ीकरण के साथ मोदी सरकार मध्यम वर्ग को सशक्त कर उसकी क्षमता में वृद्धि करने के लिए प्रतिबद्ध है। इससे न केवल हर वर्ग सुदृढ़ होगा, बल्कि 'विकसित भारत @2047' के लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए अनेक नए संभावनाओं के द्वार खुलेंगे।

ध्यातव्य है कि अभूतपूर्व ढंग से बढ़े नॉन परफॉर्मिंग एसेट (एनपीए) तथा घोर निराशा में डूबे कॉर्पोरेट क्षेत्र के साथ टूटी-फूटी अर्थव्यवस्था विरासत में मिलने के बावजूद मोदी सरकार सकारात्मक वित्तीय प्रबंधन करने में सफल रही है। इसके लिए निवेश को बढ़ावा देना, कैपिटल एक्सपेंडिचर में धीरे-धीरे वृद्धि तथा जनसुविधाओं को लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए किए गए त्रि-आयामी कार्य पर विशेष बल दिया गया। यह इन सक्रियतापूर्ण उठाए गए कदमों का ही परिणाम है कि कोविड वैश्विक महामारी के फलस्वरूप जब पूरा विश्व अनियंत्रित मुद्रास्फीति और आर्थिक मंदी के बीच फंसा हुआ है, तब भारत आज विश्व पटल पर एक चमकता सितारा के रूप में उभरा है। विश्व की सबसे तेज विकास दर वाली बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में आज राष्ट्र वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण को जन-जन की आकांक्षाओं को पूर्ण करने वाला भविष्योन्मुखी बजट प्रस्तुत करने के लिए बधाई दे रहा है। निश्चित ही यह बजट 'विकसित भारत' के पथ को प्रशस्त करेगा। ■

shivshaktibakshi@kamalsandesh.org

दिल्ली में खिला 'आप' की करा

दिल्ली विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने कहा था, "आप-दा नहीं सहेंगे, बदल के रहेंगे।" दिल्ली की जनता ने भी आप-दा को सहने से इनकार कर दिया। भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली विधानसभा चुनाव में ऐतिहासिक विजय प्राप्त की। 27 साल के बाद पार्टी ने 70 सदस्यीय दिल्ली विधानसभा में दो-तिहाई से भी अधिक बहुमत प्राप्त किया। पिछली बार के मुकाबले इस बार भाजपा ने 6 गुना अधिक 48 सीटों पर जीत हासिल की, वहीं पिछली बार 62 सीटें जीतनेवाली आम आदमी पार्टी को महज 22 सीटों से संतोष करना पड़ा। कांग्रेस को एक भी सीट नहीं मिली। भाजपा को अपने सहयोगी दलों के साथ सर्वाधिक 47 प्रतिशत से अधिक, आप को 43.57 प्रतिशत एवं कांग्रेस को 6.34 प्रतिशत मत मिले। विदित हो कि दिल्ली विधानसभा के चुनाव 5 फरवरी को हुए थे, वहीं 8 फरवरी को नतीजे आए थे।

इस चुनाव में आप के राष्ट्रीय संयोजक एवं दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, मंत्री सौरभ भारद्वाज, पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन सहित पार्टी के कई बड़े नेताओं को हार का मुंह देखना पड़ा। मुख्यमंत्री आतिशी बमुश्किल अपनी सीट बचा पाई।

दिल्ली विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी, भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं केंद्रीय मंत्री श्री जगत प्रकाश नड्डा, रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह तथा भाजपा के अन्य वरिष्ठ नेताओं ने जनसभाओं को संबोधित किया एवं रोड शो में भाग लेकर दिल्ली में भाजपा की शानदार जीत को सुनिश्चित किया।

पिछली बार के मुकाबले इस बार भाजपा ने 6 गुना अधिक 48 सीटों पर जीत हासिल की, वहीं पिछली बार 62 सीटें जीतनेवाली आम आदमी पार्टी को महज 22 सीटों से संतोष करना पड़ा। कांग्रेस को एक भी सीट नहीं मिली

भाजपा नेताओं ने अपने भाषण में 'आप' के दस साल के सत्ता काल में राशन कार्ड घोटाला, शीशमहल घोटाला, शराब घोटाला, मोहल्ला क्लीनिक घोटाला, अर्बन नक्सली सोच, जहरीला पानी, टूटी सड़कें, कूड़े के ढेर, ओवर फ्लो सीवर, प्रदूषित हवा जैसे मुद्दों को उठाया, साथ ही 'विकसित दिल्ली' का नारा देते हुए यमुनाजी को दिल्ली शहर की पहचान और इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत बनाने

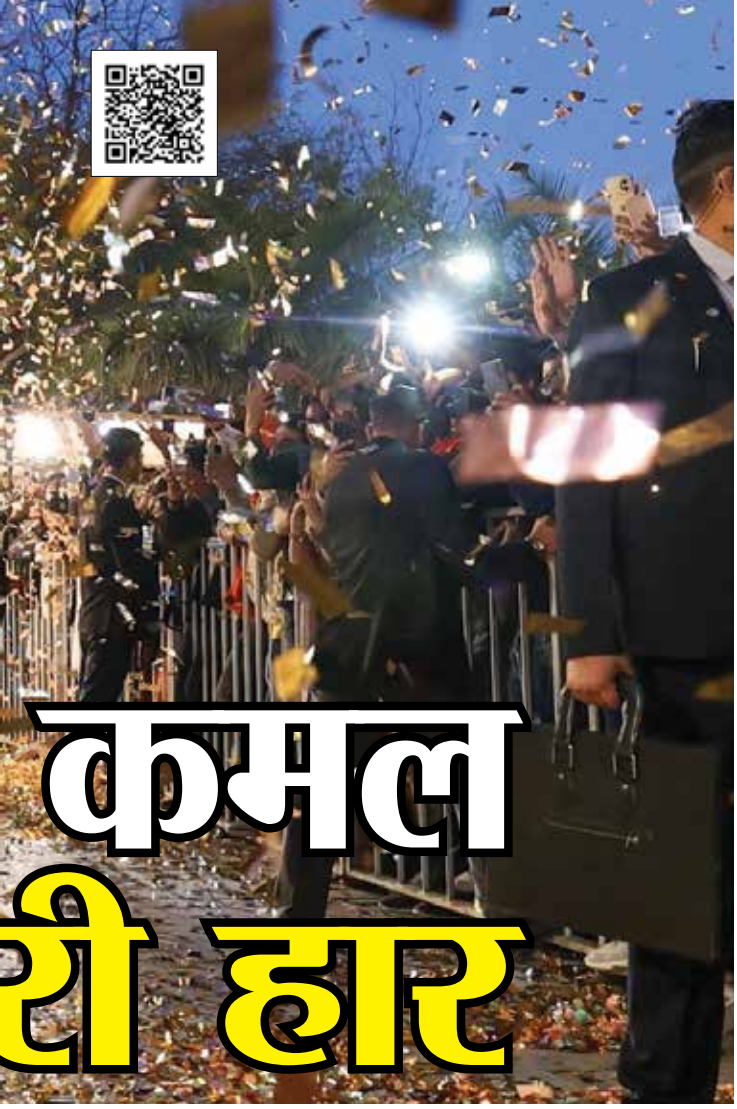

कमल ी हार

के लिए दिल्लीवासियों से भाजपा की 'डबल इंजन' की सरकार बनाने का आह्वान किया।

दिल्ली विधानसभा चुनाव में भाजपा की जीत पर प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि दिल्ली में भाजपा की आज की विजय ऐतिहासिक है। ये सामान्य विजय नहीं है क्योंकि दिल्ली की जनता ने आप-दा को बाहर कर दिया है। करीब एक दशक की आप-दा से दिल्ली मुक्त हुई है। दिल्ली का जनादेश स्पष्ट है। आज दिल्ली में विकास, विजन और विश्वास की जीत हुई है तथा आडंबर, अराजकता, अहंकार और दिल्ली पर छाई आप-दा की हार हुई है। उन्होंने कहा कि देशभर के भाजपा कार्यकर्ताओं और दिल्ली के भाजपा कार्यकर्ताओं के मन में ये टीस थी दिल्ली की पूरी तरह से सेवा न कर पाने की। आज दिल्ली ने हमारा वो आग्रह भी मान लिया। दिल्ली की युवा पीढ़ी और 21वीं सदी में पैदा हुए युवा पहली बार दिल्ली में भाजपा का सुशासन देखेंगे। लोकसभा चुनाव की जीत के बाद हमने पहले हरियाणा में अभूतपूर्व रिकॉर्ड बनाया। फिर महाराष्ट्र में नया रिकॉर्ड बनाया। अब दिल्ली में नया इतिहास रच गया है।

भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने एक के बाद एक

जनशक्ति सर्वोपरि!

विकास जीता, सुशासन जीता।

दिल्ली के अपने सभी भाई-बहनों को भाजपा को ऐतिहासिक जीत दिलाने के लिए मेरा वंदन और अभिनंदन! आपने जो भरपूर आशीर्वाद और स्नेह दिया है, उसके लिए आप सभी का हृदय से बहुत-बहुत आभार।

दिल्ली के चौतरफा विकास और यहां के लोगों का जीवन उत्तम बनाने के लिए हम कोई कोर-कसर नहीं छोड़ेंगे, यह हमारी गारंटी है। इसके साथ ही हम यह भी सुनिश्चित करेंगे कि 'विकसित भारत' के निर्माण में दिल्ली की अहम भूमिका हो।

मुझे भाजपा के अपने सभी कार्यकर्ताओं पर बहुत गर्व है, जिन्होंने इस प्रचंड जनादेश के लिए दिन-रात एक कर दिया। अब हम और भी अधिक मजबूती से अपने दिल्लीवासियों की सेवा में समर्पित रहेंगे।

- नरेन्द्र मोदी, प्रधानमंत्री

लगातार विजय हासिल की है और जनता ने 'मोदी की गारंटी' पर लगातार बारंबार मुहर लगाई है। विधानसभा चुनाव में 48 सीटों पर कमल खिलाकर यह स्पष्ट संदेश दिया है कि दिल्ली के दिल में मोदी बसता है। गरीब, पीड़ित और शोषित वर्ग के जीवन में सुधार लाने के लिए श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में जो कार्य हुए हैं, उन पर इस चुनाव में जनता ने अपनी मुहर लगाई है। उन्होंने कहा कि दिल्ली विधानसभा का यह चुनाव परिणाम आम आदमी पार्टी के कट्टर बेईमान नेताओं और उनकी पार्टी को करारा जवाब है। आम आदमी पार्टी के नेताओं ने दिल्ली को कूड़े के ढेर में बदल दिया है। जिन्होंने शुद्ध पानी देने का वादा किया था, उन्होंने ही दिल्ली की जनता को गंदा पानी पीने पर मजबूर कर दिया। जो लोग वर्ल्ड क्लास शिक्षा के नाम पर जनता को छलते थे, उन्हीं लोगों ने स्कूलों में दो-तिहाई बच्चों को विज्ञान की पढ़ाई से वंचित किया। जिन लोगों ने बेहतर सड़कों का वादा किया था, उन्होंने दिल्ली की जनता को गड्ढों से भरी सड़कों पर चलने को मजबूर किया। यही कारण है कि

दलवार परिणाम	
दल	**सीट**
भारतीय जनता पार्टी – भाजपा	48
आम आदमी पार्टी – आप	22
कुल	**70**

'आप-दा' मुक्त दिल्ली!

आज दिल्ली विधानसभा चुनाव के परिणाम में भारतीय जनता पार्टी की प्रचण्ड विजय आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में सेवा, सुशासन, गरीब कल्याण, अंत्योदय व विकासपरक नीतियों पर जनता-जनार्दन के अटूट समर्थन की जीत है। प्रत्येक बूथ पर अथक परिश्रम करने वाले भाजपा के हमारे कार्यकर्ताओं और प्रदेश नेतृत्व को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं।

'आप-दा' सरकार ने दिल्ली में भ्रष्टाचार, कुशासन, और तुष्टीकरण की सारी सीमाएं लांघ दी थी। आज दिल्ली उनके झूठ, छल और प्रपंच से मुक्त होकर प्रगति और प्रतिष्ठा के नए युग में अपनी यात्रा आरंभ कर रही है। यह जनादेश 'विकसित दिल्ली-विकसित भारत' के हमारे संकल्प को साकार स्वरूप प्रदान करेगा।

इस प्रचण्ड विजय के लिए मैं प्रधानमंत्री जी के प्रति आभार प्रकट करता हूं और समस्त भाजपा कार्यकर्ताओं और दिल्लीवासियों का अभिनंदन करता हूं।

- जगत प्रकाश नड्डा, भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष

समाचार-पत्रों की सुर्खियां

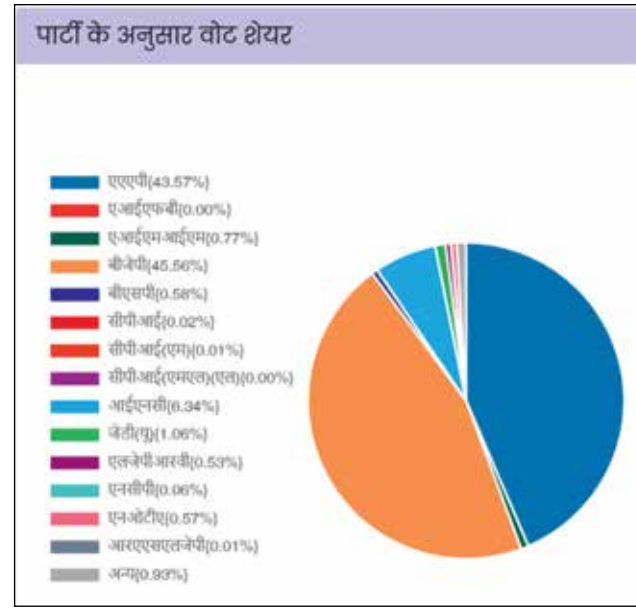

दिल्ली के विधानसभा चुनावों में भाजपा की जबरदस्त विजय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व और भाजपा की नीतियों के प्रति विश्वास की जीत है। इस देश की जनता का भरोसा मोदीजी की विश्वसनीयता और भाजपा की सुशासन और विकास की राजनीति में है।

इस शानदार जीत के लिए मैं प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी, पार्टी अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा, दिल्ली प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष श्री वीरेंद्र सचदेवा एवं सभी पार्टी कार्यकर्ताओं को हार्दिक बधाई देता हूं।

लगभग 27 साल बाद दिल्ली की जनता ने भाजपा को अपना विश्वास और आशीर्वाद दिया है। इसके लिए दिल्ली की जनता के प्रति मैं अपना आभार व्यक्त करता हूं।

विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने के लिए विकसित दिल्ली अति आवश्यक है। इस जीत के बाद डबल इंजन की सरकार दिल्ली के विकास को नई गति को बुलंदी प्रदान करेगी।

- राजनाथ सिंह, रक्षा मंत्री

इस चुनाव में दिल्ली की जनता ने स्पष्ट संदेश दिया है कि उन्हें केवल वादे करने वाली पार्टी की जरूरत नहीं है। जनता ने आम आदमी पार्टी को करारी हार देकर घर बैठाया है।

दिल्ली विधानसभा चुनाव में भाजपा की विजय पर दिल्ली प्रदेश भाजपाध्यक्ष श्री वीरेन्द्र सचदेवा ने अपने 'एक्स' पोस्ट में कहा कि यह प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी की गारंटी पर जनता के अटूट विश्वास का परिणाम है। उन्होंने कहा कि दिल्ली की जनता ने एक बार फिर यह स्पष्ट कर दिया कि माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी की गारंटी ही विश्वास और विकास की गारंटी है। इस जीत में भाजपा के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं केंद्रीय मंत्री श्री जगत प्रकाश नड्डा जी के कुशल सांगठनिक नेतृत्व व प्रबंधन और माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी की सशक्त कार्यशैली पर जनता के अटूट भरोसे की झलक भी स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। यह ऐतिहासिक परिणाम दिल्ली की जनता के अपार समर्थन और देवतुल्य कार्यकर्ताओं के अद्वितीय समर्पण व अथक परिश्रम का सजीव प्रमाण है। भारतीय जनता पार्टी को सेवा का अवसर देने पर समस्त दिल्लीवासियों का हृदय से आभार एवं अभिनंदन! ■

दिल्ली के दिल में मोदी!

दिल्ली की जनता ने झूठ, धोखे और भ्रष्टाचार के 'शीशमहल' को नेस्तनाबूत कर दिल्ली को आप-दा मुक्त करने का काम किया है।

दिल्ली ने वादाखिलाफी करने वालों को ऐसा सबक सिखाया है, जो देशभर में जनता के साथ झूठे वादे करने वालों के लिए मिसाल बनेगा।

यह दिल्ली में विकास और विश्वास के एक नए युग का आरंभ है।

दिल्ली में झूठ के शासन का अंत हुआ है... यह अहंकार और अराजकता की हार है।

यह 'मोदी की गारंटी' और मोदी जी के विकास के विजन पर दिल्लीवासियों के विश्वास की जीत है।

इस प्रचंड जनादेश के लिए दिल्ली की जनता का दिल से आभार।

मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा अपने सभी वादे पूरे कर दिल्ली को विश्व की नंबर 1 राजधानी बनाने के लिए संकल्पित है।

दिल्लीवासियों ने बता दिया कि जनता को बार-बार झूठे वादों से गुमराह नहीं किया जा सकता। जनता ने अपने वोट से गंदी यमुना, पीने का गंदा पानी, टूटी सड़कें, ओवरफ्लो होते सीवरों और हर गली में खुले शराब के ठेकों का जवाब दिया है।

दिल्ली में मिली इस भव्य जीत के लिए अपना दिन-रात एक करने वाले भाजपा दिल्ली प्रदेश के सभी कार्यकर्ताओं, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा जी और प्रदेश अध्यक्ष श्री वीरेन्द्र सचदेवा जी को हार्दिक बधाई देता हूं।

चाहे महिलाओं का सम्मान हो, अनधिकृत कॉलोनीवासियों का स्वाभिमान हो या स्वरोजगार की अपार संभावनाएं, मोदी जी के नेतृत्व में दिल्ली अब एक आदर्श राजधानी बनेगी।

- अमित शाह, केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री

'दिल्ली में विकास, विजन एवं विश्वास की जीत तथा आडंबर, अराजकता, अहंकार एवं दिल्ली पर छाई आप-दा की हार'

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 8 फरवरी, 2025 को दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 में भारतीय जनता पार्टी की ऐतिहासिक जीत पर नई दिल्ली स्थित केंद्रीय कार्यालय में आयोजित कार्यकर्ता अभिनंदन समारोह को संबोधित किया और दिल्ली के विकास के लिए भाजपा सरकार के विजन को जनता से साझा करते हुए दिल्ली के विकास को अवरुद्ध करने वाली विपक्षी पार्टियों पर जमकर प्रहार किया। कार्यक्रम में भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा, केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह सहित पार्टी के कई वरिष्ठ नेतागण, केंद्रीय मंत्री, दिल्ली प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सहित कई पार्टी पदाधिकारी, दिल्ली के भाजपा सांसद, कई नवनिर्वाचित विधायक एवं बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता उपस्थित थे। प्रधानमंत्रीजी ने अपने उद्बोधन की शुरुआत 'यमुना मैया की जय' के नारे के साथ की

कार्यकर्ता अभिनंदन समारोह को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि आज दिल्ली में दिल्ली के लोगों में एक उत्साह भी है और सुकून भी है। उत्साह विजय का है और सुकून दिल्ली को आप-दा से मुक्त कराने का है। दिल्ली के विकास की बड़ी बाधा दूर हो गई। चुनाव से पूर्व मैंने हर दिल्लीवासी के नाम पत्र भेजकर प्रार्थना की थी कि 21वीं सदी में भाजपा को अवसर दीजिए और दिल्ली को विकसित भारत की राजधानी बनाने के लिए भाजपा को मौका दीजिए। दिल्ली की जनता ने दिल खोलकर प्यार दिया। मैं दिल्ली के हर परिवारजन को मोदी की गारंटी पर भरोसा करने के लिए सिर झुकाकर नमन करता हूं। आपके इस प्यार को विकास के लॉन्ग रूट पर हम लौटाएंगे। दिल्ली के लोगों का ये प्यार और विश्वास हम सभी पर एक कर्ज है। दिल्ली की 'डबल इंजन' सरकार दिल्ली का डबल तेजी से विकास करके ये कर्ज चुकाएगी।

दिल्ली में नया इतिहास रच गया

श्री मोदी ने कहा कि दिल्ली में भाजपा की आज की विजय ऐतिहासिक है। ये सामान्य विजय नहीं है क्योंकि दिल्ली की जनता ने आप-दा को बाहर कर दिया है। करीब एक दशक की आप-दा से दिल्ली मुक्त हुई है। दिल्ली का जनादेश स्पष्ट है। आज दिल्ली में विकास, विजन और विश्वास की जीत हुई है तथा आडंबर, अराजकता, अहंकार और दिल्ली पर छाई आप-दा की हार हुई है। उन्होंने कहा कि जिन्हें दिल्ली का मालिक होने का घमंड था, उनका आज सच से सामना हो भी गया है। दिल्ली के जनादेश से स्पष्ट है कि राजनीति में शॉर्ट कट के लिए, झूठ और फरेब के लिए कोई जगह नहीं है। जनता ने शॉर्ट कट वाली राजनीति का शॉर्ट सर्किट कर दिया है।

श्री मोदी ने कहा कि देशभर के भाजपा कार्यकर्ताओं और दिल्ली के भाजपा कार्यकर्ताओं के मन में ये टीस थी दिल्ली की पूरी तरह से सेवा न कर पाने की। आज दिल्ली ने हमारा वो आग्रह भी मान लिया। दिल्ली की युवा पीढ़ी और 21वीं सदी में पैदा हुए युवा पहली बार दिल्ली में भाजपा का सुशासन देखेंगे। लोकसभा चुनाव की जीत के बाद हमने पहले हरियाणा में अभूतपूर्व रिकॉर्ड बनाया। फिर महाराष्ट्र में नया रिकॉर्ड बनाया। अब दिल्ली में नया इतिहास रच गया है।

श्री मोदी ने कहा कि आज दिल्ली का कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जहां कमल न खिला हो। हर भाषा और हर राज्य के लोगों ने दिल्ली में भाजपा के कमल निशान पर वोट दिया। चुनाव में मैं जहां गया, गर्व से कहता था कि मैं तो पूर्वांचल से सांसद हूं। ये पूर्वांचल के लोगों ने इस रिश्ते को प्यार की, विश्वास की नई ऊर्जा और ताकत दे दी। मैं पूर्वांचल के लोगों का पूर्वांचल के सांसद के नाते विशेष आभार व्यक्त करता हूं। दिल्ली वालों को मेरी गारंटी है, सबका साथ-सबका विकास-पूरी दिल्ली का विकास।

तुष्टीकरण नहीं, संतुष्टीकरण

श्री मोदी ने कहा कि आज देश तुष्टीकरण नहीं, बल्कि भाजपा के

संतुष्टीकरण की पॉलिसी को चुन रहा है। टकराव तथा प्रशासनिक अनिश्चितता ने दिल्ली का बहुत नुकसान किया है। आज दिल्ली के विकास के सामने से एक रुकावट आप सब दिल्लीवासियों ने दूर कर दी है।

एनडीए की गारंटी मतलब सुशासन की गारंटी

श्री मोदी ने कहा कि पूरा देश जानता है कि जहां एनडीए है, वहां सुशासन है, विकास है और विश्वास है। एनडीए का हर उम्मीदवार, हर जनप्रतिनिधि लोगों के हित में काम करता है। देश में एनडीए को जहां जनादेश मिला है, हमने उस राज्य को विकास की नई ऊंचाई पर पहुंचाया है। इसलिए भाजपा को लगातार जीत मिल रही है। लोग हमारी सरकारों को दूसरी बार, तीसरी बार चुन रहे हैं। उत्तराखंड, हरियाणा, उत्तरप्रदेश, एमपी, गोवा, महाराष्ट्र, असम, अरुणाचल, मणिपुर, बिहार हर राज्य में हमें दोबारा सत्ता मिली है।

उन्होंने कहा कि एनडीए की गारंटी मतलब सुशासन की गारंटी। इसका फायदा गरीब को भी होता है और मिडिल क्लास को भी। दिल्ली में गरीब, झुग्गी में रहने वाले भाई-बहन और मिडिल क्लास ने भाजपा को जबरदस्त समर्थन दिया है। हर वर्ग के बहुत सारे प्रोफेशनल हमारी पार्टी में काम कर रहे हैं। इसका कारण यह है कि हमारी पार्टी ने हमेशा मिडिल क्लास को अपनी प्राथमिकता पर रखा है।

नारी शक्ति का आशीर्वाद

श्री मोदी ने कहा कि देश की नारीशक्ति का आशीर्वाद हमारा सबसे बड़ा रक्षा कवच है। एक बार फिर नारीशक्ति ने दिल्ली में मुझे अपना आशीर्वाद दिया है। मैं दिल्ली की मातृशक्ति से कहता हूं कि मैं उनसे किया हर वादा पूरा करूंगा। ये मोदी की गारंटी है, यानी गारंटी के पूरा होने की गारंटी है।

दिल्ली-एनसीआर के हर प्रदेश में भाजपा का शासन

श्री मोदी ने कहा कि दिल्ली के लोग टूटती सड़कें, कूड़े के ढेर, सीवर ओवरफ्लो और प्रदूषित हवा से त्रस्त रहे हैं। अब यहां भाजपा सरकार दिल्ली को विकास की ऊर्जा के साथ एक आधुनिक शहर बनाएगी। पहली बार दिल्ली-एनसीआर के हर प्रदेश में भाजपा का शासन आया है।

यमुनाजी को दिल्ली की पहचान बनाएंगे

मां यमुना की दुर्दशा पर गहरा दुःख प्रकट करते हुए श्री मोदी ने कहा कि मां यमुना हमारी आस्था का केंद्र हैं। तभी तो कहते हैं कि 'नमो नमस्ते यमुना सदा त्वम।' हम लोग हमारा सदा मंगल करने वाली यमुना को नमस्कार करते हैं। उसी यमुना जी की इन लोगों ने कैसी दुर्दशा कर दी है। दिल्ली का तो अस्तित्व ही मां यमुनाजी की गोद में पनपा है। दिल्ली के लोग यमुना की इस पीड़ा को देखकर आहत हो रहे हैं, लेकिन दिल्ली की आप-दा ने इस आस्था का अपमान किया, लोगों की भावनाओं-आस्था को पैरों तले कुचल दिया। अपनी नाकामी के लिए हरियाणा के लोगों पर इतना बड़ा आरोप लगा दिया। चुनाव प्रचार के दौरान मैंने संकल्प लिया है कि यमुनाजी को हम दिल्ली शहर की पहचान बनाएंगे।

आप-दा वाले कट्टर बेईमान निकले

श्री मोदी ने कहा कि आप-दा वाले यह कहकर राजनीति में आए थे कि राजनीति बदल डालेंगे, लेकिन ये कट्टर बेईमान निकले। वरिष्ठ महानुभाव श्रीमान अन्ना हजारे का बयान सुन रहा था। वे काफी समय से इन आप-दा वालों के कुकर्मों की पीड़ा झेल रहे थे। आज उन्हें भी उस पीड़ा से मुक्ति मिली होगी। इस पार्टी का जन्म ही भ्रष्टाचार के विरुद्ध हुए आंदोलन से हुआ हो, वही भ्रष्टाचार में लिप्त हो गई। यह देश की ऐसी पार्टी बनी जिसके मुख्यमंत्री, मंत्री भ्रष्टाचार के आरोप में जेल गए। ये खुद को ईमानदारी का सर्टिफिकेट और दूसरों को भ्रष्टाचार का मेडल देते थे, वे खुद बेईमान निकले। शराब घोटाले ने दिल्ली को बदनाम किया। अहंकार इतना कि जब दुनिया कोरोना से निपट रही थी, तब ये आप-दा वाले शीशमहल बना रहे थे। आप-दा वालों ने अपने घोटाले छिपाने के लिए साजिशें रचीं। मैं गारंटी दे रहा हूं कि पहले विधानसभा सत्र में ही सीएजी की रिपोर्ट सदन में रखी जाएगी। भ्रष्टाचार की जांच होगी और जिसने भी लूटा है, उसको लौटाना पड़ेगा। ये भी मोदी की गारंटी है।

कांग्रेस ने जीरो की डबल हैट्रिक लगाई

कांग्रेस पर कड़ा हमला करते हुए श्री मोदी ने कहा कि आज जनता ने फिर एक बार कांग्रेस को कड़ा संदेश दिया है। दिल्ली के चुनाव में कांग्रेस ने जीरो की डबल हैट्रिक लगाई है। देश की राजधानी में देश की सबसे पुरानी पार्टी का लगातार दिल्ली में 6 बार से खाता नहीं खुल रहा है। ये लोग खुद गोल्ड मेडल देते फिर रहे हैं। सच्चाई यह है कि कांग्रेस पर देश बिल्कुल भरोसा करने को तैयार नहीं है। कांग्रेस परजीवी पार्टी बन चुकी है। खुद तो डूबती है, अपने साथियों को भी डुबोती है। कांग्रेस के नेता कहते हैं कि वो इंडियन स्टेट से लड़ रहे हैं, ये अर्बन नक्सलियों की भाषा है। ये देश में, समाज में अराजकता लाने की भाषा है। आप-दा भी उसी सोच को आगे बढ़ा रही थी।

भाजपा की रिफॉर्म-परफॉर्म की गारंटी

श्री मोदी ने कहा कि दिल्ली में भाजपा की ये ऐतिहासिक जीत हमारे लिए नई जिम्मेदारी लेकर आई है। भाजपा रिफॉर्म-परफॉर्म की गारंटी देती है। इसमें दिल्लीवासी जुड़ जायेंगे तो ट्रांसफॉर्मेशन और तेजी से आएगा। हम मिलकर दिल्ली को विकसित भारत की विकसित राजधानी बनाएंगे। हम सत्ता सुख के लिए नहीं, सेवा भाव के लिए आए हैं। हम शक्ति और समय सेवा के लिए खपा देंगे। इस संकल्प के साथ हम आगे बढ़ें। ■

भाजपा की सरकार दिल्ली में भी विकास करके दिखाएगी: जगत प्रकाश नड्डा

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं केन्द्रीय मंत्री श्री जगत प्रकाश नड्डा ने 8 फरवरी, 2025 को नई दिल्ली स्थित केंद्रीय कार्यालय में दिल्ली विधानसभा चुनाव में भाजपा की ऐतिहासिक जीत पर प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की गरिमामय उपस्थिति में आयोजित समारोह को संबोधित किया। श्री नड्डा ने श्री मोदी का अभिनंदन करते हुए भाजपा को भरपूर आशीर्वाद देने के लिए दिल्ली की जनता के प्रति आभार और दिल्ली प्रदेश के जुझारू कार्यकर्ताओं के प्रति साधुवाद व्यक्त किया। कार्यक्रम के दौरान मंच पर प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी एवं केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह उपस्थित रहे

भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने एक के बाद एक लगातार विजय हासिल की है और जनता ने 'मोदी की गारंटी' पर लगातार, बारंबार मुहर लगाई है। विधानसभा और लोकसभा दोनों ही चुनाव में दिल्ली की जनता स्पष्ट संदेश दिया। लोकसभा में दिल्ली की जनता ने सभी सातों सीटों पर भाजपा को विजयी बनाने के बाद अब विधानसभा चुनाव में 48 सीटों पर कमल खिलाकर यह स्पष्ट संदेश दिया है कि दिल्ली के दिल में मोदी बसता है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने पिछले 10 वर्षों में देश की राजनीति में एक बड़ा परिवर्तन लाया है। देश को भ्रष्टाचार और जातिवाद से निकालकर विकास और प्रगति की ओर अग्रसर किया है। गरीब, पीड़ित और शोषित वर्ग के जीवन में सुधार लाने के लिए श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में जो कार्य हुए हैं, उन पर इस चुनाव में जनता ने अपनी मुहर लगाई है। भारतीय राजनीति में पहले लोभ-लुभावने वादों का बोलबाला था। जनता को लुभाने के लिए बड़े-बड़े वादे किए जाते थे, जो बाद में भुला दिए जाते थे, लेकिन प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने इस परंपरा को बदलते हुए राजनीति में रिपोर्ट कार्ड की परंपरा शुरू की। उन्होंने जो कहा उसे पूरा करके दिखाया, और जो नहीं कहा था, वह भी पूरा किया। यही कारण है कि आज जन-जन की जुबान पर एक ही नारा है 'मोदी की गारंटी, यानी गारंटी पूरी होने की गारंटी।'

श्री नड्डा ने कहा कि दिल्ली विधानसभा का यह चुनाव परिणाम आम आदमी पार्टी के कट्टर बेईमान नेताओं और उनकी पार्टी को करारा जवाब है। आम आदमी पार्टी के नेताओं ने दिल्ली को कूड़े के ढेर में बदल दिया है। जो लोग चुनाव से पहले कूड़े के पहाड़ पर खड़े होकर उसे खत्म करने के वादे करते थे, वही लोग आज दिल्ली के हर घर के सामने कूड़े का ढेर लगाने के जिम्मेदार हैं। जिन्होंने शुद्ध पानी देने का वादा किया था, उन्होंने ही दिल्ली की जनता को गंदा पानी पीने पर मजबूर कर दिया। जो लोग वर्ल्ड क्लास शिक्षा के नाम पर जनता को छलते थे, उन्हीं लोगों ने स्कूलों में दो-तिहाई बच्चों को विज्ञान की पढ़ाई से वंचित किया। जिन लोगों ने बेहतर सड़कों का वादा किया था, उन्होंने दिल्ली की जनता को गड्ढों से भरी सड़कों पर चलने को मजबूर किया। यही कारण है कि इस चुनाव में दिल्ली की जनता ने स्पष्ट संदेश दिया है कि उन्हें केवल वादे करने वाली पार्टी की जरूरत नहीं है। जनता ने आम आदमी पार्टी को करारी हार देकर घर बैठाया है।

श्री नड्डा ने कहा कि अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी झूठ बोलने की फैक्ट्री, झूठ बोलने की एनसाइक्लोपीडिया और झूठ की संपदा वाली आपदा भी है। यह पार्टी भ्रष्टाचार की नई-नई तकनीकें निकालने वाली पार्टी है और वास्तव में आप-दा ही है। दिल्ली की जनता ने चुनाव में 'आप'दा को करारी हार दिखाकर यह साफ कर दिया है कि इस ऐतिहासिक जीत के माध्यम से प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में दिल्ली फिर से विकास की

प्रमुख बिंदु

- 'आप-दा' वाली यह पार्टी झूठ की फैक्ट्री और एनसाइक्लोपीडिया है।
- दिल्ली विधानसभा का चुनाव परिणाम आम आदमी पार्टी के कट्टर बेईमान नेताओं को करारा जवाब है। केजरीवाल की हार यह स्पष्ट करती है कि दिल्ली की जनता ने शराब घोटाले में उन्हें जेल भेजने पर अपनी मुहर लगा दी है।
- आप-दा ने दिल्ली में कूड़े के ढेर लगाए, लोगों को गंदा पानी पीने पर मजबूर किया, स्कूलों में पढ़ने वाले दो तिहाई बच्चों को विज्ञान की पढ़ाई से वंचित रखा, लोगों को गड्ढों वाली सड़कों पर चलने पर मजबूर किया।
- 'आप' नेता जो खुद को 'कट्टर ईमानदार' कहते थे, वे ही कट्टर भ्रष्टाचारी निकले।
- 2014 के बाद से कांग्रेस का दिल्ली विधानसभा और लोकसभा चुनाव स्कोर हमेशा शून्य ही रहा है।

दिशा में आगे बढ़ेगी। जो खुद को 'कट्टर ईमानदार' कहते थे, वे ही कट्टर भ्रष्टाचारी निकले। मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, मंत्री और विधायक सभी जेल की हवा खा चुके हैं। आम आदमी पार्टी की हार यह स्पष्ट करती है कि दिल्ली की जनता ने उन्हें जेल भेजने पर अपनी मुहर लगा दी है। दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजों में जिस तरह से महिलाओं, युवाओं, बुजुर्गों और व्यवसायियों ने साथ दिया है, उन्हें भारतीय जनता पार्टी की ओर से बहुत-बहुत बधाई देता हूं। आप-दा के अलावा एक ऐसी पार्टी है जो अपने स्कोर में लगातार शून्य पर बनी हुई है, चाहे वह 2014 का लोकसभा चुनाव हो, 2015 का विधानसभा चुनाव, 2019 का लोकसभा चुनाव, 2020 का विधानसभा चुनाव, 2024 का लोकसभा चुनाव या फिर 2025 का विधानसभा चुनाव। कांग्रेस पार्टी का स्कोर हमेशा शून्य ही रहा है।

श्री नड्डा ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने कहा था, "आपदा नहीं सहेंगे, बदल के रहेंगे।" दिल्ली की जनता ने भी आप-दा को सहने से इनकार कर दिया और दिल्ली को बदलकर रख दिया। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा को जो विश्वास मिला है और जो वादे हमने जनता से किए थे, उन्हें भाजपा ने अपने शासित राज्यों में पूरा किया है और अब दिल्ली में भी इन्हें पूरा किया जाएगा। अब भाजपा की सरकार दिल्ली में भी विकास करके दिखाएगी। श्री नड्डा ने अंत में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के प्रति आभार एवं अभिनंदन व्यक्त किया और दिल्ली की जनता द्वारा दिए गए आशीर्वाद के लिए उन्हें हृदय से धन्यवाद दिया। ■

उत्तर प्रदेश

मिल्कीपुर उपचुनाव में भाजपा की जीत

भारतीय जनता पार्टी ने 08 फरवरी, 2025 को उत्तर प्रदेश के अयोध्या जिले की मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर शानदार विजय प्राप्त की। यहां समाजवादी पार्टी की करारी हार हुई। केंद्र एवं प्रदेश दोनों में डबल इंजन वाली सरकार की कल्याणकारी नीतियों और विकास कार्यों के कारण भाजपा को इस उपचुनाव में भारी जीत मिली। भारत के चुनाव आयोग द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार भाजपा उम्मीदवार श्री चंद्रभानु पासवान ने सपा के अजीत प्रसाद के खिलाफ 61,710 से अधिक मतों से आसान जीत हासिल की, जिससे अयोध्या क्षेत्र में पार्टी की स्थिति और मजबूत हुई है। यह जीत इतनी जोरदार थी कि सपा उम्मीदवार अपने बूथ पर भी हार गए। मिल्कीपुर से मौजूदा विधायक अवधेश प्रसाद के इस्तीफे के बाद इस सीट पर उपचुनाव संपन्न हुआ था।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने मिल्कीपुर उपचुनाव में भाजपा की जीत पर बधाई दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के अयोध्या जिले के मिल्कीपुर उपचुनाव में भाजपा की जीत पर बधाई देते हुए कहा, "आज देश तुष्टीकरण नहीं, बल्कि भाजपा की संतुष्टीकरण की नीति को चुन रहा है। आज दिल्ली के साथ-साथ अयोध्या के मिल्कीपुर में भी भाजपा को जीत मिली है। हर वर्ग ने बड़ी संख्या में भाजपा को वोट दिया है।"

भाजपा की कल्याणकारी नीतियों एवं विकास कार्यों के लिए अटूट समर्थन: जगत प्रकाश नड्डा

उपचुनाव में जीत के बाद भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं केंद्रीय मंत्री श्री जगत प्रकाश नड्डा ने बधाई देते हुए कहा, "उत्तर प्रदेश में अयोध्या जिले की मिल्कीपुर विधानसभा के उपचुनाव में भाजपा की प्रचण्ड जीत आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के मार्गदर्शन में डबल इंजन सरकार की जन-कल्याणकारी नीतियों एवं विकास कार्यों पर जनता के अटूट समर्थन का प्रतीक है। इस विजय के लिए उत्तर प्रदेश, भाजपा के सभी कार्यकर्ताओं का अभिनंदन एवं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी जी को बधाई देता हूं।" ■

1 लाख रुपए तक प्रति माह की औसत आय पर कोई आयकर नहीं

- वेतनभोगी करदाताओं को नई कर व्यवस्था में 12.75 लाख रुपए तक कोई आयकर नहीं देना होगा
- प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना से 1.7 करोड़ किसान लाभान्वित होंगे, इनमें 100 निम्न उत्पादन वाले जिलों को शामिल किया जाएगा
- अरहर, उड़द व मसूर पर विशेष ध्यान देते हुए 'दालों में आत्मनिर्भरता मिशन' शुरू किया जाएगा
- संशोधित ब्याज योजना के तहत केसीसी के माध्यम से पांच लाख रुपए तक का लोन
- एमएसएमई को गारंटी के साथ दिए जाने वाले ऋण को 5 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 10 करोड़ रुपए किया गया
- वित्त वर्ष-25 में राजकोषीय घाटा 4.8 प्रतिशत रहने का अनुमान, इसे वित्त वर्ष-26 में 4.4 प्रतिशत करने का लक्ष्य
- अगले पांच वर्षों में सरकारी स्कूलों में 50 हजार अटल टिंकरिंग प्रयोगशालाएं
- गिग वर्करों को पहचान पत्र दिया जाएगा, पीएम जन आरोग्य योजना के तहत ई-श्रम पोर्टल और स्वास्थ्य देखभाल में पंजीकरण
- विकास केन्द्र के रूप में शहरों को एक लाख करोड़ रुपये का शहरी चुनौती निधि
- 20 हजार करोड़ रुपए परिव्यय के साथ लघु मॉड्यूलर रिएक्टरों के आरएंडडी के लिए अणु ऊर्जा मिशन
- निजी क्षेत्र द्वारा संचालित शोध विकास व नवाचार पहलों के लिए 20 हजार करोड़ रुपए आवंटित
- बीमा क्षेत्र में एफडीआई की सीमा 74 से बढ़ाकर 100 प्रतिशत किया गया
- विभिन्न कानूनों में 100 से ज्यादा प्रावधानों को गैर-अपराधीकरण रूप देते हुए जन विश्वास विधेयक 2.0 लाया जाएगा
- कैंसर, असाधारण रोगों और अन्य गंभीर जीर्ण रोगों के उपचार के लिए 36 जीवनरक्षक औषधियों को बुनियादी सीमा-शुल्क (बीसीडी) से छूट

केन्द्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने 01 फरवरी, 2025 को संसद में केन्द्रीय बजट 2025-26 पेश किया। तेलुगु कवि और नाटककार श्री गुराजादा अप्पा राव के प्रसिद्ध कथन 'कोई देश केवल उसकी मिट्टी से नहीं है, बल्कि देश उसके लोगों से है' कथन को उद्धृत करते हुए वित्त मंत्री ने केन्द्रीय बजट 2025-26 में प्रस्तुत किया। इसमें 'सबका विकास' लक्ष्य के साथ समस्त क्षेत्रों का संतुलित विकास का लक्ष्य रखा गया है।

इसी लक्ष्य के अनुरूप वित्त मंत्री ने विकसित भारत के व्यापक सिद्धांतों का उल्लेख किया जो इस तरह से हैं—

क) गरीबी से मुक्ति
ख) शत-प्रतिशत अच्छे स्तर की स्कूली शिक्षा
ग) बेहतरीन, सस्ती और सर्वसुलभ स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच
घ) शत-प्रतिशत कुशल कामगार के साथ सार्थक रोजगार
ङ) आर्थिक गतिविधियों में 70 प्रतिशत महिलाएं
च) हमारे देश को 'फूड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड' बनाने वाले किसान

केन्द्रीय बजट 2025-26 में विकास को बढ़ावा के लिए सरकारी प्रयासों को जारी रखने, समग्र विकास को सुनिश्चित करने, निजी क्षेत्र में निवेश को बढ़ाने, परिवारिक भावनाओं को बढ़ाने और उभरते मध्यम वर्ग की व्यय क्षमता को बढ़ाने का वादा किया गया। इस बजट में प्रस्तावित विकास उपाय, गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी को ध्यान में रखकर किया गया है।

बजट में भारत की विकास संभावनाओं और वैश्विक प्रतिस्पर्धा में वृद्धि के लिए कराधान, ऊर्जा क्षेत्र, ग्रामीण विकास, खनन, वित्तीय क्षेत्र और नियामक में परिवर्तनकारी सुधारों का लक्ष्य रखा गया है। बजट की मुख्य बातें इस प्रकार हैं:

भाग- ए

बजट अनुमान 2025-26

- उधारियों के अलावा कुल प्राप्तियां और कुल व्यय क्रमशः 34.96 लाख करोड़ रुपये तथा 50.65 लाख करोड़ रुपये रहने का अनुमान है।
- निवल कर प्राप्तियां 28.37 लाख करोड़ रुपये रहने का अनुमान है।
- राजकोषीय घाटा जीडीपी का 4.4 प्रतिशत रहने का अनुमान है।
- सकल बाजार उधारियां 14.82 लाख करोड़ रुपये रहने का अनुमान है।
- वित्त वर्ष 2025-26 में कैपेक्स व्यय 11.21 लाख करोड़ रुपये (जीडीपी का 3.1 प्रतिशत) रहने का अनुमान है।

विकास के प्रथम इंजन के रूप में कृषि

प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना – विकासशील कृषि जिला कार्यक्रम

- राज्यों की भागीदारी से 'प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना' का शुभारंभ करेगी। इस कार्यक्रम में मौजूदा योजनाओं और विशिष्ट उपायों के अभिसरण के माध्यम से कम उत्पादकता, कम उपज और औसत से कम ऋण मानदण्डों वाले 100 जिलों

को शामिल किया जाएगा। इस कार्यक्रम से 1.7 करोड़ किसानों को मदद मिलने की संभावना है।

ग्रामीण समृद्धि और लचीला निर्माण

- राज्यों की भागीदारी से 'ग्रामीण समृद्धि और लचीला निर्माण' नामक एक व्यापक बहु-क्षेत्रीय कार्यक्रम प्रारम्भ किया जाएगा ताकि कौशल, निवेश, प्रौद्योगिकी के माध्यम से कृषि में कम रोजगार का समाधान होगा और ग्रामीण अर्थव्यवस्था में नई जान आएगी।
- पहले चरण में 100 विकासशील कृषि जिलों को शामिल किया जाएगा।

दलहन में आत्मनिर्भरता

- सरकार तूर, उड़द और मसूर पर विशेष ध्यान देने के साथ 6 वर्षीय 'दलहनों में आत्मनिर्भरता मिशन' प्रारम्भ करेगी।
- केंद्रीय एजेंसियां नेफेड और एनसीसीएफ अगले 4 वर्षों के दौरान किसानों से ये दालें खरीदेगी।

सब्जियों और फलों के लिए व्यापक कार्यक्रम

- उत्पादन, प्रभावी आपूर्तियों, प्रसंस्करण और किसानों के लिए लाभकारी मूल्य को बढ़ावा देने के लिए राज्यों की भागीदारी से एक व्यापक कार्यक्रम का शुभारंभ किया जाएगा।

बिहार में मखाना बोर्ड

- मखानों का उत्पादन, प्रसंस्करण, मूल्य संवर्धन और विपणन में सुधार लाने के लिए बिहार में मखाना बोर्ड स्थापित किया जाएगा।

राष्ट्रीय उच्च पैदावार बीज मिशन

- राष्ट्रीय उच्च पैदावार बीज मिशन शुरू किया जाएगा, जिसका उद्देश्य अनुसंधान इकोसिस्टम को मजबूत करना, लक्षित विकास और उच्च पैदावार वाले बीजों का प्रसार करना और बीजों की 100 से अधिक किस्मों को वाणिज्यिक स्तर पर उपलब्ध कराना होगा।

किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से अधिक ऋण

- किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से लिए जाने वाले ऋणों के लिए ऋण सीमा 3 लाख रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपये कर दी जाएगी।

विकास के दूसरे इंजन के रूप में एमएसएमई

एमएसएमई के वर्गीकरण मानदण्ड में संशोधन

- सभी एमएसएमई के वर्गीकरण के लिए निवेश और कारोबार की सीमा बढ़ाकर क्रमशः 2.5 और 2 गुना कर दी जाएगी।

सूक्ष्म उद्यमों के लिए क्रेडिट कार्ड

- उद्यम पोर्टल पर पंजीकृत सूक्ष्म उद्यमों के लिए पहले वर्ष में 5 लाख रुपये तक की सीमा वाले 10 लाख कस्टमाइज्ड क्रेडिट कार्ड जारी किए जाएंगे।

स्टार्ट-अप के लिए निधियों का कोष

- विस्तारित कार्यक्षेत्र और 10,000 करोड़ रुपए के नए अंशदान के साथ निधियों के नए कोष की स्थापना की जाएगी।

पहली बार के उद्यमियों के लिए योजना

- 5 लाख महिलाओं अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के पहली बार के उद्यमियों के लिए अगले 5 वर्षों के दौरान 2 करोड़ रुपए तक का सावधि ऋण उपलब्ध कराने की एक नई योजना की घोषणा।

खिलौना क्षेत्र के लिए उपाय

- भारत को 'वैश्विक खिलौना केंद्र' बनाते हुए उच्च गुणवत्ता वाले अनूठे नवीन और पर्यावरण के अनुकूल खिलौने बनाने की योजना।

खाद्य प्रसंस्करण के लिए सहायता

- बिहार में राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमशीलता और प्रबंधन संस्थान स्थापना की जाएगी।

विनिर्माण मिशन - 'मेक इन इंडिया' को आगे बढ़ाना

- 'मेक इन इंडिया' को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से लघु, मध्यम और बड़े उद्योगों को शामिल करते हुए राष्ट्रीय विनिर्माण मिशन की स्थापना की जाएगी।

विकास के तीसरे इंजन के रूप में निवेश

I. लोगों में निवेश

सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0

- पोषण संबंधी सहायता के लिए लागत मानदण्डों को समुचित रूप से बढ़ाया जाएगा।

अटल टिंकरिंग प्रयोगशालाएं

- अगले 5 वर्षों में सरकारी स्कूलों में 50,000 अटल टिंकरिंग प्रयोगशालाएं स्थापित की जाएंगी।

भारतीय भाषा पुस्तक स्कीम

- स्कूल और उच्चतर शिक्षा के लिए भारतीय भाषाओं में डिजिटल रूप में पुस्तकें प्रदान करने के लिए भारतीय भाषा पुस्तक योजना की घोषणा।

राष्ट्रीय कौशल उत्कृष्टता केंद्र

- 'मेक फॉर इंडिया मेक फॉर द वर्ल्ड' विनिर्माण के लिए हमारे युवाओं को आवश्यक कौशलों से सुसज्जित करने के लिए वैश्विक

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की केंद्रीय बजट 2025-26 पर टिप्पणी

लोगों की जेब भरने वाला बजट

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने एक फरवरी को वीडियो संदेश के माध्यम से केंद्रीय बजट 2025-26 पर अपनी टिप्पणी दी। आज के दिन को भारत के विकास की यात्रा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर बताते हुए श्री मोदी ने कहा कि यह बजट 140 करोड़ भारतीयों की आकांक्षाओं को प्रतिबिंबित करता है और हर नागरिक के सपनों को पूरा करता है। उन्होंने कहा कि युवाओं के लिए कई क्षेत्र खोले गए हैं और आम नागरिक 'विकसित भारत' के मिशन को आगे बढ़ाएंगे। प्रधानमंत्री ने जोर देकर कहा कि यह बजट एक ऐसा फोर्स मल्टीप्लायर (बल गुणक) है, जो बचत, निवेश, खपत और विकास को बढ़ाएगा। उन्होंने 'लोगों के बजट' के लिए केंद्रीय वित्त और कॉर्पोरेट कार्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण और उनकी टीम को बधाई दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि आमतौर पर बजट का ध्यान सरकार के खजाने को भरने पर होता है, लेकिन इस बजट में नागरिकों की जेब भरने, उनकी बचत बढ़ाने और उन्हें देश के विकास में भागीदार बनाने पर ध्यान केंद्रित किया गया है। उन्होंने जोर देकर कहा कि यह बजट इन लक्ष्यों की नींव रखता है।

श्री मोदी ने कहा, "इस बजट में सुधारों की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं।" उन्होंने परमाणु ऊर्जा में निजी क्षेत्र को बढ़ावा देने के ऐतिहासिक फैसले पर प्रकाश डाला। श्री मोदी ने आगे कहा कि भविष्य में असैन्य परमाणु ऊर्जा देश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान सुनिश्चित करेगी। उन्होंने जोर देकर कहा कि बजट में सभी रोजगार क्षेत्रों को प्राथमिकता दी गई है।

आने वाले समय में महत्वपूर्ण बदलाव लाने वाले दो बड़े सुधारों का उल्लेख करते हुए श्री मोदी ने कहा कि जहाज निर्माण को अवसंरचना का दर्जा देने से भारत में बड़े जहाजों के निर्माण को बढ़ावा मिलेगा, 'आत्मनिर्भर भारत' अभियान में तेजी आएगी। अवसंरचना की श्रेणी में 50 पर्यटन स्थलों पर होटलों को शामिल करने से पर्यटन को काफी बढ़ावा मिलेगा, जिससे आतिथ्य क्षेत्र, जो सबसे बड़ा रोजगार क्षेत्र है, को नई ऊर्जा मिलेगी।

प्रधानमंत्री ने कहा कि देश 'विकास भी, विरासत भी' के मंत्र के साथ आगे बढ़ रहा है। उन्होंने उल्लेख किया कि ज्ञान भारतम मिशन के शुभारंभ के माध्यम से एक करोड़ पांडुलिपियों को संरक्षित करने के लिए इस बजट में महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। इसके अतिरिक्त, भारतीय ज्ञान परंपराओं से प्रेरित एक राष्ट्रीय डिजिटल भण्डार बनाया जाएगा।

श्री मोदी ने कहा कि बजट में किसानों के लिए की गई घोषणाएं कृषि क्षेत्र और पूरी ग्रामीण अर्थव्यवस्था में नई क्रांति की नींव रखेंगी। उन्होंने इस बात को रेखांकित किया कि प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना के तहत 100 जिलों में सिंचाई और अवसंरचना का विकास किया जाएगा। श्री मोदी ने जोर देकर कहा कि किसान क्रेडिट कार्ड की सीमा 3 लाख रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपये करने से किसानों को अधिक सहायता प्राप्त होगी।

12 लाख रुपये तक की आय 'कर मुक्त'

श्री मोदी ने उल्लेख किया कि बजट में 12 लाख रुपये तक की आय को कर से मुक्त रखा गया है। उन्होंने कहा कि सभी आय वर्गों के लिए कर में कटौती की गई है, जिससे मध्यम वर्ग और नई नौकरी पाने वालों को बहुत लाभ होगा।

प्रधानमंत्री ने जोर देकर कहा, "बजट में उद्यमियों, एमएसएमई

और छोटे व्यवसायों को मजबूत करने और नई नौकरियां पैदा करने के लिए विनिर्माण पर 360 डिग्री यानि संपूर्ण ध्यान केंद्रित किया गया है।" उन्होंने कहा कि स्वच्छ प्रौद्योगिकी, चमड़ा, फुटवियर और खिलौना उद्योग जैसे क्षेत्रों को राष्ट्रीय विनिर्माण मिशन के तहत विशेष समर्थन मिला है। श्री मोदी ने जोर देकर कहा कि लक्ष्य स्पष्ट है कि भारतीय उत्पाद वैश्विक बाजार में अपनी चमक बिखेरें।

इस बात पर जोर देते हुए कि बजट में राज्यों में एक जीवंत और प्रतिस्पर्धी निवेश वातावरण बनाने पर विशेष जोर दिया गया है, श्री मोदी ने एमएसएमई और स्टार्टअप के लिए ऋण गारंटी को दोगुना करने की घोषणा पर प्रकाश डाला। उन्होंने एससी, एसटी और पहली बार के उद्यमियों के लिए बिना गारंटी के 2 करोड़ रुपये तक का ऋण प्रदान करने की योजना की शुरुआत का उल्लेख किया।

गिग वर्कर्स को स्वास्थ्य सेवा और अन्य सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ

श्री मोदी ने गिग वर्कर्स के लिए महत्वपूर्ण घोषणा पर जोर दिया, जिसके तहत पहली बार ई-श्रम पोर्टल पर उनका पंजीकरण किया जाएगा गया, जिससे वे स्वास्थ्य सेवा और अन्य सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ उठाने में सक्षम होंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि यह श्रम की गरिमा के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को प्रतिबिंबित करता है। उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि जन विश्वास 2.0 जैसे विनियामक और वित्तीय सुधार न्यूनतम सरकार और विश्वास-आधारित शासन के प्रति प्रतिबद्धता को मजबूत करेंगे।

अपने संबोधन का समापन करते हुए प्रधानमंत्री ने टिप्पणी की कि यह बजट न केवल देश की वर्तमान जरूरतों का समाधान करता है, बल्कि भविष्य की तैयारी में भी मदद करता है। उन्होंने डीप टेक फंड, भू-स्थानिक मिशन और परमाणु ऊर्जा मिशन सहित स्टार्टअप के लिए घोषणा की गई पहल पर प्रकाश डाला। उन्होंने इस ऐतिहासिक बजट के लिए सभी नागरिकों को बधाई दी। ■

बजट में गरीब, किसान व मध्यम वर्ग के कल्याण को प्राथमिकता दी गई है: जगत प्रकाश नड्डा

आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी द्वारा आज प्रस्तुत किया गया आम बजट संतुलित, समावेशी और विकास को बढ़ावा देने वाला है। यह बजट 'विकसित भारत' के संकल्प को तीव्र गति प्रदान करेगा।

इसमें गरीब, किसान व मध्यम वर्ग के कल्याण को प्राथमिकता दी गई है। यह समावेशी व सर्वहितकारी बजट वंचितों का सम्मान सुनिश्चित करेगा और इसमें नारीशक्ति व मध्यम वर्ग का उत्थान समाहित है।

मैं हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रति आभार व्यक्त करता हूं और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी एवं उनकी टीम को दूरदर्शी तथा भविष्योन्मुखी, विकासोन्मुखी और सर्वसमावेशी बजट पेश करने के लिए बधाई देता हूं। ■

विशेषज्ञता और भागीदारी के साथ 5 राष्ट्रीय कौशल उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किये जाएंगे।

चिकित्सा शिक्षा का विस्तार

- मेडिकल कॉलेजों और अस्पतालों में अगले 5 वर्षों में 75,000 और सीटें बढ़ाने के लक्ष्य की दिशा में अगले वर्ष 10,000 अतिरिक्त सीटें बढ़ाई जाएंगी।

सभी जिला अस्पतालों में डे-केयर कैंसर केंद्र

- सरकार अगले 3 वर्षों में सभी जिला अस्पतालों में डे-केयर कैंसर केंद्र स्थापित करने की सुविधा प्रदान करेगी। वर्ष 2025-26 में 200 केंद्र स्थापित किए जाएंगे।

पीएम स्वनिधि

- इस स्कीम को बैंकों से संवर्धित ऋण 30,000 रुपए की सीमा के साथ यूपीआई लिंक्ड क्रेडिट कार्डों और क्षमता विकास सहायता के साथ नवीकृत किया जाएगा।

II. अर्थव्यवस्था में निवेश

अवसंरचना में सरकारी निजी भागीदारी

- सरकारी निजी भागीदारी में 3 वर्षीय पाइपलाइन परियोजनाओं के लिए अवसंरचना संबंधी मंत्रालय बनाए जाएंगे; राज्यों को भी प्रोत्साहित किया जाएगा।

अवसंरचना के लिए राज्यों को सहायता

- सुधारों के लिए पूंजी व्यय और प्रोत्साहन के लिए राज्यों को 50 वर्ष के ब्याजमुक्त ऋण के लिए डेढ़ लाख करोड़ रुपये के आवंटन का प्रस्ताव।

परिसंपत्ति मौद्रीकरण योजना 2025-30

- घोषित की गई नई परियोजनाओं में 10 लाख करोड़ रुपए की पूंजी के लिए 2025-30 के लिए दूसरी योजना।

जल जीवन मिशन

- बढ़े हुए कुल आवंटन के साथ मिशन को 2028 तक बढ़ाया गया।

शहरी चुनौती कोष

- एक लाख करोड़ रुपए के शहरी चुनौती कोष की घोषणा, जिसे 2025-26 के लिए 10 हजार करोड़ रुपए के आवंटन के प्रस्ताव के साथ वृद्धि केंद्रों के रूप में शहरों का रचनात्मक पुनर्विकास और जल एवं स्वच्छता के लिए प्रस्ताव लागू करने के लिए उपयोग किया जाएगा।

'विकसित भारत' के लिए परमाणु ऊर्जा मिशन

- परमाणु ऊर्जा अधिनियम और नागरिक दायित्व परमाणु क्षति अधिनियम में संशोधन का प्रस्ताव।
- 20 हजार करोड़ रुपए के आवंटन के साथ लघु मॉड्यूलर रियक्टर्स (एसएमआर) के अनुसंधान व विकास के लिए परमाणु ऊर्जा मिशन स्थापित किया जाएगा। 2033 तक 5 स्वदेश विकसित एसएमआर संचालित करने का प्रस्ताव।

पोत निर्माण

- पोत निर्माण वित्तीय सहायता नीति को नया रूप दिया जाएगा।
- निर्दिष्ट आकार से अधिक विशालकाय पोतों को अवसंरचना सुसंगत मास्टर लिस्ट (एचएमएल) में शामिल किया जाएगा।

उड़ान क्षेत्रीय संपर्क स्कीम

- अगले 10 वर्ष में 120 नए गंतव्यों और 4 करोड़ यात्रियों को लाने-ले-जाने के लिए क्षेत्रीय संपर्क बढ़ाने की संशोधित उड़ान स्कीम की घोषणा।

बिहार में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट

- बिहार में ग्रीन पटना एयरपोर्ट और बिहटा में ब्राउनफील्ड एयरपोर्ट की क्षमता के विस्तार के अलावा बिहार में ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट की घोषणा।

खनन क्षेत्र सुधार

- टेलिंग से महत्वपूर्ण खनिजों की रिकवरी के लिए नीति बनाई जाएगी।

रोजगार आधारित वृद्धि के लिए पर्यटन

- चुनौती मोड के जरिये राज्यों की भागीदारी से देश में 50 शीर्ष पर्यटन स्थलों को विकसित किया जाएगा।

III. नवाचार में निवेश

अनुसंधान, विकास और नवाचार

- पिछले वर्ष जुलाई के बजट में घोषित निजी क्षेत्र संचालित अनुसंधान, विकास और नवाचार पहल को लागू करने के लिए 20 हजार करोड़ रुपए आवंटित किए जाएंगे।

प्रधानमंत्री अनुसंधान फैलोशिप

- बढ़ी हुई वित्तीय सहायता के साथ आईआईटी और आईआईएस में प्रौद्योगिकीय अनुसंधान के लिए 10 हजार फैलोशिप।

ज्ञान भारतम मिशन

- शैक्षिक संस्थानों, संग्रहालयों और निजी संग्रहकर्ताओं के साथ पांडुलिपी विरासत के सर्वेक्षण, प्रलेखन और संरक्षण के लिए ज्ञान भारतम मिशन बनाने का प्रस्ताव। इसके तहत 1 करोड़ से अधिक पांडुलिपियां शामिल की जाएंगी।

विकास के चतुर्थ इंजन के रूप में निर्यात

निर्यात संवर्द्धन मिशन

- वाणिज्य मंत्रालय एमएसएमई और वित्त मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से संचालित निर्यात संवर्द्धन मिशन स्थापित करने का प्रस्ताव। इसके तहत अलग-अलग क्षेत्रों और मंत्रालयों के लिए लक्ष्य तय किए जाएंगे।

भारत ट्रेडनेट

- व्यापार प्रलेखन और वित्त पोषण समाधानों के लिए संयुक्त मंच के रूप में अंतरराष्ट्रीय व्यापार के लिए भारत ट्रेडनेट (बीटीएन) स्थापित किया जाएगा।

वित्तीय क्षेत्र सुधार और विकास

बीमा क्षेत्र में एफडीआई

- भारत में संपूर्ण प्रीमियम का निवेश करने वाली कंपनियों के लिए बीमा क्षेत्र में एफडीआई की सीमा 74 से बढ़ाकर 100 प्रतिशत की जाएगी।

एनएबीएफआईडी द्वारा क्रेडिट वृद्धि सुविधा

- एनएबीएफआईडी अवसंरचना के लिए कॉरपोरेट बॉंड के उद्देश्य से

बजट में मध्यम एवं वेतनभोगी वर्ग का विशेष ध्यान रखा गया है: राजनाथ सिंह

मैं वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण को बधाई देता हूं, जिन्होंने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के 'विकसित भारत' के संकल्प को पूरा करने की दिशा में एक शानदार बजट पेश किया है। यह बजट युवा, गरीब, किसान, नारीशक्ति के साथ-साथ समाज के सभी वर्गों एवं क्षेत्रों के विकास को बढ़ावा देने वाला है।

इस बजट में एक सर्वसमावेशी दृष्टिकोण अपनाया गया है। हमारे समाज के गरीब वर्गों को सशक्त बनाने से लेकर किसानों तक, एमएसएमई से लेकर उद्योगों तक तथा कृत्रिम बुद्धिमत्ता जैसी उन्नत तकनीकों में अनुसंधान को मजबूत करने का प्रयास किया गया है।

मुख्य रूप से मध्यम वर्ग के योगदान का ध्यान रखते हुए यह बजट अभूतपूर्व तोहफा लेकर आया है। 12 लाख रुपये तक की वार्षिक आय पर आयकर से राहत दिए जाने के निर्णय का मैं हृदयतल से स्वागत करता हूं। मैं पुनः प्रधानमंत्री जी को और वित्त मंत्री जी को इस ऐतिहासिक बजट के लिए बधाई देता हूं।

रक्षा क्षेत्र में भारत को 'आत्मनिर्भर' बनाने के प्रधानमंत्री श्री मोदी के विजन को इस बजट से और बढ़ावा मिला है। वित्त वर्ष 2025-26 के लिए रक्षा मंत्रालय के लिए 6.81 लाख करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।

रक्षा बलों पर 1,80,000 करोड़ रुपये का पूंजीगत व्यय हमारे रक्षा बलों के आधुनिकीकरण, तकनीकी उन्नति एवं क्षमता निर्माण में और मदद करेगा।

मुझे विश्वास है कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के कुशल नेतृत्व में यह बजट सुरक्षा को और मजबूत करेगा और देश की समृद्धि सुनिश्चित करेगा तथा 'विकसित भारत' के विजन को साकार करने में सहयोगी साबित होगा। ■

बजट 2025 'विकसित भारत' के निर्माण की दिशा में मोदी सरकार की दूरदर्शिता का ब्लूप्रिंट है: अमित शाह

केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने एक फरवरी को बजट 2025 को विकसित और हर क्षेत्र में श्रेष्ठ भारत के निर्माण की दिशा में मोदी सरकार की दूरदर्शिता का ब्लूप्रिंट बताया। केन्द्रीय गृह मंत्री श्री शाह ने सर्वसमावेशी और दूरदर्शी बजट के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी और वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी को बधाई दी।

एक्स प्लेटफॉर्म पर अपनी सिलसिलेवार पोस्ट्स में श्री शाह ने कहा कि बजट 2025 विकसित और हर क्षेत्र में श्रेष्ठ भारत के निर्माण की दिशा में मोदी सरकार की दूरदर्शिता का ब्लूप्रिंट है। किसान, गरीब, मध्यम वर्ग, महिला और बच्चों की शिक्षा, पोषण व स्वास्थ्य से लेकर स्टार्टअप, इनोवेशन और इंवेस्टमेंट तक, हर क्षेत्र को समाहित करता यह बजट मोदी जी के 'आत्मनिर्भर भारत' का रोडमैप है। इस सर्वसमावेशी और दूरदर्शी बजट के लिए प्रधानमंत्री श्री मोदी जी और वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमन जी को बधाई देता हूं।

केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री ने कहा कि देश का मध्यम वर्ग हमेशा प्रधानमंत्री मोदी जी के दिल में है। उन्होंने कहा कि 12 लाख रुपए तक की आय पर शून्य आयकर की प्रस्तावित छूट मध्यम वर्ग के वित्तीय कल्याण की दिशा में बेहद मददगार साबित होगी। ■

आंशिक ऋण वृद्धि सुविधा स्थापित करेगा।

जन विश्वास विधेयक 2.0

- जन विश्वास विधेयक 2.0 में 100 से अधिक प्रावधानों को गैर आपराधिक बनाने के लिए प्रस्ताव।

खंड बी

प्रत्यक्ष कर

- नई कर व्यवस्था के अन्तर्गत 12 लाख रुपए तक की आय (अर्थात विशिष्ट दर जैसे पूंजीगत लाभ को छोड़कर 1 लाख रुपये प्रतिमाह की औसत आय) पर कोई आयकर देय नहीं होगा।
- वेतनभोगी कर दाताओं के लिए यह सीमा 75 हजार रुपये की मानक कटौती के कारण 12.75 लाख रुपये होगी।
- यह नई संरचना मध्यम वर्ग के करों को काफी कम करेगी और घरेलू उपयोग, बचत तथा निवेश को बढ़ावा देने के लिए उनके पास अधिक धन राशि उपलब्ध होगी।
- नया आयकर विधेयक भी अध्यायों और शब्दों दोनों की दृष्टि से सुस्पष्ट और प्रत्यक्ष होगा। यह करदाताओं और कर प्रशासन के लिए समझने में आसान होगा, जिससे कर सुनिश्चितता आएगी और मुकदमेबाजी कम होगी।

प्रत्यक्ष करों में लगभग एक लाख करोड़ रुपये का परित्याग होगा।

संशोधित कर संरचना

- नई कर व्यवस्था में संशोधित कर संरचना निम्नानुसार होगी।

0-4 लाख रुपए	शून्य
4-8 लाख रुपए	5 प्रतिशत
8-12 लाख रुपए	10 प्रतिशत
12-16 लाख रुपए	15 प्रतिशत
16-20 लाख रुपए	20 प्रतिशत
20-24 लाख रुपए	25 प्रतिशत
24 लाख रुपए से अधिक	30 प्रतिशत

टीडीएस/टीसीएस को तर्क संगत बनाना

- टीडीएस की दरों और सीमाओं की संख्या कम कर उसे तर्क संगत बनाना।
- वरिष्ठ नागरिकों के लिए ब्याज पर कटौती की सीमा 50,000 रुपये से दो गुनी बढ़ाकर 1 लाख रुपये की जा रही है।
- किराये पर टीडीएस के लिए वार्षिक सीमा 2.40 लाख रुपये से बढ़ाकर छह लाख रुपये की गई।

अनुपालन बोझ को कम करना

- छोटे धर्मार्थ न्यासों/संस्थाओं की पंजीकृत अवधि को बढ़ाकर 5 वर्ष से 10 वर्ष कर ऐसी संस्थाओं के अनुपालन संबंधी बोझ को कम किया गया।
- कर दाताओं को अपने स्वामित्व वाली संपत्तियों के लिए शून्य वार्षिक मूल्य का दावा बिना किसी शर्त के ऐसी दो संपत्तियों के लाभ की अनुमति का प्रस्ताव।

व्यवसाय करने की सुगमता

- तीन वर्षों की ब्लॉक अवधि के लिए अंतराष्ट्रीय लेन-देन के मामलों में आर्म्स लेन्थ मूल्य निर्धारण करते हेतु एक योजना की शुरुआत।
- अंतरराष्ट्रीय कराधान में विवादों को कम करने तथा निश्चितता को बनाए रखने के लिए सेफ हार्बर नियमों के दायरे का विस्तार।
- 29 अगस्त, 2024 को या उससे पश्चात व्यक्तियों द्वारा राष्ट्रीय बचत स्कीम (एनएसएस) से किए गए आहरण पर छूट।
- एनपीएस वात्सल्य खातों के लिए भी ऐसी ही व्यवस्था का प्रस्ताव, जो समग्र सीमाओं के अधीन सामान्य एनपीएस खातों के लिए उपलब्ध है।

रोजगार एवं निवेश

इलेक्ट्रॉनिकी विनिर्माण स्कीमों के लिए निश्चितता

- उन अनिवासियों के लिए प्रकल्पित कराधान व्यवस्था का प्रस्ताव जो ऐसी निवासी कंपनी को सेवाएं प्रदान करते हैं जो इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण सुविधा स्थापित या संचालित कर रही है।
- विशिष्ट इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण इकाइयों की आपूर्ति के लिए उपकरण घटकों को स्टोर करने वाले अनिवासियों की कर निश्चितता के लिए सुरक्षित बंदरगाह सेवा आरंभ की गई है।

अन्तर्देशीय जहाजों के लिए टन भार योजना

- देश में अन्तर्देशीय जल परिवहन को बढ़ावा देने के लिए मौजूदा टन भार कर योजना के लाभों को भारतीय पोत अधिनियम 2021 के अंतर्गत पंजीकृत अन्तर्देशीय जलयानों के लिए विस्तारित करने का प्रस्ताव किया गया है।

स्टार्ट-अप के निगमन का विस्तार

- 1.4.2030 से पहले निगमित होने वाले भारतीय स्टार्ट-अप इको-सिस्टम को 5 वर्षों तक अवधि का विस्तार कर स्टार्ट-अप लाभ प्रदान किए गए हैं।

अप्रत्यक्ष कर

औद्योगिक वस्तुओं के सीमा शुल्क ढांचे का युक्तिकरण

केंद्रीय बजट 2025-26 के प्रस्तावों में

1. 7 टैरिफ दरों को हटाने का प्रस्ताव किया गया है। यह 2023-24 के बजट में हटाई गई सात टैरिफ दरों के अतिरिक्त है। इसके बाद शेष बची टैरिफ दरें 'शून्य' दर सहित आठ रह जाएंगी।

2. मोटे तौर पर प्रभावी शुल्क दायित्व बनाए रखने के लिए कुछ मदों, जहां ऐसा दायित्व मामूली रूप से कम होगा, को छोड़कर उपयुक्त कर लगाने का प्रस्ताव है।
3. एक से अधिक उपकर अथवा अधिभार न लगाने का प्रस्ताव है। उपकर के अधीन 82 टैरिफ लाइनों पर समाज कल्याण अधिभार से छूट दी जाएगी।

अप्रत्यक्ष करों में 2,600 करोड़ रुपये के राजस्व का परित्याग होगा

औषधि/दवाओं के आयात पर राहत

- 36 जीवन रक्षक औषधियों और दवाओं को बुनियादी सीमा शुल्क से पूरी तरह छूट।
- 6 जीवन रक्षक दवाएं 5 प्रतिशत के रियायती सीमा-शुल्क दवाओं में शामिल।
- औषधि कंपनियों द्वारा चलाए जाने वाले रोगी सहायता कार्यक्रमों के अंतर्गत विशिष्ट औषधियां और दवाएं बुनियादी सीमा शुल्क से पूरी तरह मुक्त। 13 नए रोगी सहायता कार्यक्रमों के साथ ही 37 अन्य दवाओं को इसमें शामिल करने का प्रस्ताव।

घरेलू विनिर्माण और मूल्य वर्धन को सहायता

महत्वपूर्ण खनिज

- कोबाल्ट पाउडर और लिथियम आयन बैट्री के अवशिष्ट, लेड, जिंक और 12 अन्य महत्वपूर्ण खनिजों पर बुनियादी सीमा शुल्क में छूट।

वस्त्र

- घरेलू तकनीकी वस्त्र उत्पादों को बढ़ावा।
- दो अन्य प्रकार के शटल-रहित करघों वाली टेक्सटाइल मशीनरी सीमा शुल्क से मुक्त।
- बुने हुए वस्त्रों पर 10 प्रतिशत या 20 प्रतिशत के बुनियादी सीमा शुल्क को संशोधित कर 20 प्रतिशत अथवा 115 रुपये प्रति किलोग्राम में जो भी अधिक हो करने का प्रस्ताव।

इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं

- इन्टेरेक्टिव फ्लैट पैनल डिस्प्ले पर बुनियादी सीमा शुल्क 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 20 प्रतिशत किया गया।
- ओपेन सेल्स और अन्य घटकों पर बुनियादी सीमा शुल्क घटाकर 5 प्रतिशत करने का प्रस्ताव।
- ओपेन सेल्स के अन्य घटकों पर बुनियादी सीमा शुल्क में छूट।

लिथियम आयन बैट्री

- इलेक्ट्रिक वाहनों के बैट्री के विनिर्माण के लिए 35 अतिरिक्त पूंजीगत वस्तुओं और मोबाइल फोन बैट्री विनिर्माण हेतु 28 अतिरिक्त पूंजीगत वस्तुओं पर छूट।

पोत परिवहन क्षेत्र

- पोत निर्माण में कच्चे माल, घटकों, उपभोज्यों अथवा पुर्जों पर अगले दस वर्षों तक बुनियादी सीमा शुल्क में छूट।
- पुराने पोतों के लिए भी ऐसी ही छूट।

दूरसंचार

- कैरियर ग्रेड इथरनेट स्वीच पर बुनियादी सीमा शुल्क 20 प्रतिशत से 10 प्रतिशत पर लाया गया।

निर्यात संवर्धन

हस्तशिल्प वस्तुएं

- हस्तशिल्प की निर्यात अवधि 6 महीने से बढ़ाकर एक वर्ष की गई, आवश्यकता पड़ने पर आगे तीन महीनों के लिए और बढ़ाई जा सकती है।
- शुल्क मुक्त वस्तुओं की सूची में नौ और वस्तुएं शामिल की गईं।

चमड़े की वस्तुएं

- वेट ब्लू लेदर पर बुनियादी सीमा शुल्क में पूर्ण छूट।
- क्रश लेदर को 20 प्रतिशत निर्यात शुल्क से छूट।

समुद्री उत्पाद

- फ्रोजन फिश पेस्ट (सुरीमी) और ऐसे ही उत्पादों के निर्यात पर बुनियादी सीमा शुल्क 30 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत किया गया।
- मछली और झींगा के आहार बनाने के लिए फिश हाइड्रोलीसेट पर बुनियादी सीमा शुल्क 15 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत किया गया।
- ऐसी वस्तुओं के निर्यात की समय-सीमा छह महीने से बढ़ाकर एक वर्ष की गई, जिसे आगे एक वर्ष और बढ़ाई जा सकती है।

व्यापार सुविधा

- प्रोविजनल कर निर्धारण की समय-सीमा।
- व्यवसाय प्रोविजनल कर निर्धारण को अंतिम रूप देने के लिए दो वर्ष की समय-सीमा तय करने का प्रस्ताव, जिसे एक वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है।

स्वैच्छिक अनुपालन

- आयातक या निर्यातक की सुविधा के लिए माल की मंजूरी के बाद स्वेच्छा से महत्वपूर्ण तथ्यों की घोषणा कर सकते हैं और जुर्माने के बिना ब्याज सहित शुल्क का भुगतान कर सकते हैं। ■

वित्त वर्ष 2026 में वास्तविक जीडीपी में 6.3 फीसदी से 6.8 फीसदी की दर से वृद्धि का अनुमान

- वित्त वर्ष 2025 में भारत की वास्तविक जीडीपी और जीवीए वृद्धि दर के 6.4 फीसदी रहने का अनुमान
- वित्त वर्ष 2026 में वास्तविक जीडीपी में 6.3 फीसदी से 6.8 फीसदी की दर से वृद्धि का अनुमान
- पूंजीगत व्यय (कैपेक्स) में वित्त वर्ष 2021 से वित्त वर्ष 2024 तथा आम चुनाव के बाद तक निरंतर वृद्धि हुई है, यह जुलाई-नवंबर, 2024 के दौरान 8.2 फीसदी की दर बढ़ी है
- खुदरा मुद्रा स्फीति वित्त वर्ष 2024 के 5.4 फीसदी से घटकर अप्रैल-दिसंबर, 2024 में 4.9 फीसदी रह गई
- अनुसूचित व्यवसायिक बैंकों का जीएनपीए घटकर 2.6 फीसदी के स्तर पर, जो 12 वर्षों में सबसे कम है
- वित्त वर्ष 2025 के पहले 9 महीनों में कुल निर्यात में 6 फीसदी (वर्ष दर वर्ष) की वृद्धि
- दूरसंचार, कम्प्यूटर तथा सूचना, सेवा क्षेत्र में भारत पूरी दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक
- विदेशी मुद्रा 640.3 बिलियन डॉलर जो 10.9 महीनों के आयात तथा बाहरी ऋण के लगभग 90 फीसदी को पूरा करने के लिए पर्याप्त
- स्मार्ट फोन आयात में भारी गिरावट, अब 99 फीसदी विनिर्माण घरेलू स्तर पर
- विश्व स्तर पर शीर्ष 10 पैटेंट दाखिल करने वाले कार्यालयों में भारत छठें स्थान पर
- वित्त वर्ष 2025 के अप्रैल-नवंबर के दौरान भारत की सेवा निर्यात वृद्धि दर 12.1 फीसदी रही, जो वित्त वर्ष 2024 के 5.7 फीसदी की तुलना में तेज वृद्धि दर्शाती है
- 2024 में खरीफ खाद्यान्न उत्पादन के 1647.05 एलएमटी पर पहुंचने की उम्मीद, पिछले वर्ष की तुलना में 89.37 एलएमटी की वृद्धि
- गैर-जीवाश्म ईंधन स्रोत से स्थापित विद्युत उत्पादन क्षमता, कुल उत्पादन क्षमता की 46.8 फीसदी है
- वित्त वर्ष 2021 से वित्त वर्ष 2025 के दौरान सामाजिक क्षेत्र व्यय में 15 फीसदी की वार्षिक वृद्धि दर दर्ज की गई
- सरकारी स्वास्थ्य खर्च 29.0 फीसदी से बढ़कर 48.0 फीसदी हुआ, लोगों के कुल स्वास्थ्य खर्च में जेब से होने वाले खर्च की हिस्सेदारी वित्त वर्ष 2015 से वित्त वर्ष 2022 के बीच 62.6 फीसदी से घटकर 39.4 फीसदी रह गई
- बेरोजगारी दर 2017-18 के 6 फीसदी से घटकर 2023-24 में 3.2 फीसदी रह गई

केंद्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने 31 जनवरी को संसद में आर्थिक समीक्षा 2024-25 पेश की। समीक्षा की मुख्य बातें निम्न हैं:

अर्थव्यवस्था की स्थिति: फिर से तेज विकास दर

1. भारत की वास्तविक जीडीपी वृद्धि वित्त वर्ष 2025 में 6.4 फीसदी रहने की उम्मीद (राष्ट्रीय आय के अग्रिम अनुमान के अनुसार), जो दशक के औसत के नजदीक है।
2. वैश्विक अर्थव्यवस्था 2023 में 3.3 फीसदी की दर से बढ़ी, आईएमएफ ने अगले 5 वर्षों के लिए 3.2 फीसदी वृद्धि का अनुमान लगाया था।
3. वित्त वर्ष 2026 में वास्तविक जीडीपी वृद्धि 6.3 से 6.8 के बीच बढ़ेगी, वृद्धि के उतार-चढ़ाव को ध्यान में रखते हुए।
4. जमीनी स्तर पर संरचनात्मक सुधारों पर जोर तथा विनियमन को कम करने से मध्य अवधि वृद्धि क्षमता सुदृढ़ होगी और भारतीय अर्थव्यवस्था की वैश्विक प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा मिलेगा।
5. भू-राजनैतिक तनाव अभी जारी संघर्ष तथा वैश्विक व्यापार नीतिगत जोखिम वैश्विक आर्थिक परिदृश्य में गंभीर चुनौती बने हुए हैं।
6. खुदरा मुद्रा स्फीति (हेडलाइन) वित्त वर्ष 2024 के 5.4 फीसदी से घटकर अप्रैल-दिसंबर, 2024 में 4.9 प्रतिशत रह गई।
7. पूंजीगत व्यय (कैपेक्स) में वित्त वर्ष 2021 से वित्त वर्ष 2024 के दौरान निरंतर सुधार हुआ है, आम चुनावों के बाद कैपेक्स में जुलाई-नवंबर, 2024 के दौरान 8.2 फीसदी की वृद्धि (वर्ष दर वर्ष) दर्ज की गई।

मौद्रिक और वित्तीय क्षेत्र से जुड़े तथ्य

1. बैंक ऋण में स्थिर गति से वृद्धि हुई है और यह जमा राशि के लगभग बराबर हो गई है।
2. अनुसूचित व्यवसायिक बैंकों की सकल गैर-निष्पादित परिसम्पत्तियां (डीएनपीए) घटकर सितंबर, 2024 के अंत में सकल ऋण और अग्रिम के 2.6 फीसदी पर आ गई है, जो 12 वर्षों का निम्न स्तर है।
3. दिवाला और दिवालियापन संहिता के अंतर्गत सितंबर, 2024 तक 1068 योजनाओं के समाधान से 3.6 लाख करोड़ रुपये प्राप्त किए गए।
4. प्राथमिक बाजारों (इक्विटी और ऋण) से प्राप्त पूंजी संग्रह अप्रैल से दिसंबर, 2024 के दौरान 11.1 लाख करोड़ रहा, जो वित्त वर्ष 2024 के दौरान जुटाई गई धनराशि से 5 फीसदी अधिक है।

बाहरी क्षेत्र: एफडीआई बेहतर हो रहा है

1. वैश्विक अनिश्चितताओं और प्रतिकूल परिस्थितियों के बीच भारत का बाहरी क्षेत्र सुदृढ़ बना हुआ है।
2. वित्त वर्ष 2025 के पहले 9 महीनों में कुल निर्यात में (व्यापार+सेवा)

6 प्रतिशत (वर्ष दर वर्ष) की वृद्धि दर्ज की गई।

3. वित्त वर्ष 2025 की दूसरी तिमाही में भारत का चालू खाता घाटा जीडीपी का 1.2 फीसदी रहा, जिसे नेट सेवा प्राप्तियों की वृद्धि तथा निजी अंतरण प्राप्तियों में वृद्धि से समर्थन मिला है।
4. वित्त वर्ष 2025 में सकल विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफडीआई) में मजबूती आई है, जो वित्त वर्ष 2024 के पहले 8 महीनों के 47.2 बिलियन डॉलर से बढ़कर वित्त वर्ष 2025 की सामान अवधि के लिए 55.6 बिलियन डॉलर हो गया है, इसमें 17.9 फीसदी की वर्ष दर वर्ष वृद्धि दर्ज की गई है।
5. दिसंबर, 2024 के अंत में भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 640.3 बिलियन डॉलर है, 10.9 महीनों के आयात तथा देश के बाहरी ऋण के 90 फीसदी के लिए पर्याप्त है।
6. भारत का बाहरी ऋण पिछले कुछ वर्षों से स्थिर रहा है; सितंबर, 2024 के अंत में बाहरी ऋण और जीडीपी का अनुपात 19.4 फीसदी रहा है।

मूल्य और मुद्रा स्फीतिः समीकरण को समझना

1. आईएमएफ के अनुसार वैश्विक मुद्रा स्फीति दर 2024 में 5.7 फीसदी रही, जो 2022 में 8.7 फीसदी के शीर्ष पर थी।
2. भारत में खुदरा मुद्रा स्फीति वित्त वर्ष 2024 के 5.4 फीसदी के मुकाबले वित्त वर्ष 2025 (अप्रैल-दिसंबर, 2024) में घटकर 4.9 फीसदी रह गई।
3. आरबीआई और आईएमएफ का अनुमान है कि भारत की उपभोक्ता मूल्य स्फीति वित्त वर्ष 2026 में 4 फीसदी लक्ष्य के अनुरूप रहेगी।
4. जलवायु-सहनीय फसल किस्मों और कृषि तौर-तरीकों में सुधार, तीव्र जलवायु घटनाओं के प्रभावों को कम करने और दीर्घावधि में मूल्य स्थिरता हासिल करने के लिए आवश्यक है।

मध्य अवधि दृष्टिः विनियमन में कमी से विकास को गति

1. वर्ष 2047 तक विकसित भारत के विज़न को प्राप्त करने के लिए भारत को अगले एक दशक या दो दशकों तक औसतन स्थिर मूल्य पर लगभग 8 प्रतिशत की वृद्धि दर हासिल करने की जरूरत है।
2. भारत घरेलू विकास को बढ़ावा देने के लिए प्रणालीगत विनियमन में कमी पर ध्यान केन्द्रित करेगा तथा लोगों और संगठनों को वैध आर्थिक गतिविधि को आसानी से संचालित करने के लिए सशक्त बनाएगा।
3. अगले कदम के रूप में राज्यों को मानकों तथा नियंत्रणों पर ढील देने पर काम करना चाहिए, लागू करने के लिए कानूनी सुरक्षा उपाय निर्धारित करना, टैरिफ और शुल्कों में कमी लाना, जोखिम आधारित विनियम को लागू करना।

निवेश और अवसंरचनाः निरंतर जारी रहनी चाहिए

1. पिछले पांच वर्षों में सरकार का केन्द्रीय ध्यान अवसंरचना के लिए सार्वजनिक व्यय में वृद्धि करने तथा मंजूरी व संसाधन जुटाने को गति देने पर रहा है।
2. प्रमुख अवसंरचना क्षेत्रों पर केन्द्र सरकार के पूंजीगत परिव्यय में वित्त वर्ष 2020 से वित्त वर्ष 2024 तक 38.8 फीसदी की दर से वृद्धि हुई है।
3. परिचालन दक्षता में सुधार से प्रमुख पत्तनों पर कंटेनर टर्न अराउंड अवधि में औसतन कमी दर्ज की गई है, यह अवधि वित्त वर्ष 2024 के 48.1 घंटों से घटकर वित्त वर्ष 2025 (अप्रैल-नवंबर) में 30.4 घंटे रह गई है इससे पत्तन की परिवहन सुविधा में सुधार हुआ है।
4. भारत की कुल स्थापित क्षमता में नवीकरणीय ऊर्जा की हिस्सेदारी 47 फीसदी हो गई है।
5. डीडीयूजेजीवाई और सौभाग्य जैसी सरकार की योजनाओं से ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली तक पहुंच में सुधार हुआ है, 18,374 गांवों तथा 2.9 करोड़ घरों को बिजली की सुविधा मिली।
6. जल जीवन मिशन के तहत योजना की शुरुआत से अब तक 12 करोड़ परिवारों को नल से पेय जल आपूर्ति की सुविधा मिली है।
7. शहरी क्षेत्रों में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 89 लाख आवासों का निर्माण हुआ है।
8. नगर परिवहन नेटवर्क का तेजी से विस्तार हो रहा है, 29 शहरों के 1000 किलोमीटर से अधिक के लिए मेट्रो और त्वरित रेल प्रणाली या तो परिचालन में है या निर्माण के अधीन है।
9. रियल स्टेट (विनियम और विकास) अधिनियम 2016 ने रियल स्टेट क्षेत्र के विनियमन और पारदर्शिता सुनिश्चित की; जनवरी, 2025 तक 1.38 लाख रियल स्टेट परियोजनाएं पंजीकृत की गई है तथा 1.38 लाख शिकायतों का समाधान किया गया है।
10. वर्तमान में भारत 26 सक्रिय अंतरिक्ष परिसम्पत्तियों का परिचालन करता है; सरकार के अंतरिक्ष विज़न 2047 में गगनयान मिशन तथा चंद्रयान-4, चांद सैम्पल वापसी मिशन जैसी महत्वाकांक्षी परियोजनाएं शामिल हैं।
11. केवल सार्वजनिक निवेश अवसंरचना की जरूरतों को पूरा नहीं कर सकता, अंतर को पाटने के लिए निजी क्षेत्र की भागीदारी महत्वपूर्ण है।

उद्योगः व्यापार सुधार पर विशेष ध्यान

1. विद्युत तथा निर्माण में मजबूत विकास से संचालित औद्योगिक क्षेत्र ने वित्त वर्ष 2025 (पहला अग्रिम अनुमान) में 6.2 फीसदी की वृद्धि दर्ज की।
2. वित्त वर्ष 2024 में भारतीय ऑटोमोबाइल क्षेत्र में घरेलू बिक्री में 12.5 प्रतिशत की बढ़ोतरी रही।
3. 99 प्रतिशत स्मार्टफोन अब घरेलू स्तर पर देश में निर्मित हो रहे हैं जिससे भारत की आयात पर निर्भरता उल्लेखनीय तौर पर कम हो गई है।
4. सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र में समान धन सहायता के लिए सरकार ने 50 हजार करोड़ रुपये के कोष से आत्मनिर्भर-भारत कोष स्थापित किया है।
5. सरकार देशभर में एमएसएमई क्लस्टर विकसित करने के लिए सूक्ष्म

और लघु उद्यम-क्लस्टर विकास कार्यक्रम लागू कर रही है।

सेवा क्षेत्र: पुराने योद्धा के समक्ष नई चुनौतियां

1. वर्ष 2023 में वैश्विक सेवा निर्यात में भारत 4.3 प्रतिशत साझेदारी के साथ विश्व में सातवें स्थान पर रहा।
2. भारत के सेवा निर्यात में विकास वित्त वर्ष 2024 के 5.7 प्रतिशत से बढ़कर वित्त वर्ष 2025 के (अप्रैल-नवम्बर) में 12.8 प्रतिशत की वृद्धि का अनुमान है।
3. वित्त वर्ष 2013 से वित्त वर्ष 2023 के दशक में सूचना और कम्प्यूटर आधारित सेवा में 12.8 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई। इससे सकल मूल्य वर्धन-जीवीए में उसकी हिस्सेदारी 6.3 प्रतिशत से बढ़कर 10.9 प्रतिशत हो गई है।
4. भारतीय रेलवे ने वित्त वर्ष 2024 से यातायात में 8 प्रतिशत की रिकॉर्ड बढ़ोतरी दर्ज की है, जबकि वित्त वर्ष 2024 में माल भाड़े ढुलाई में 5.2 प्रतिशत का राजस्व अर्जित किया है।
5. पर्यटन क्षेत्र का सकल घरेलू उत्पाद में योगदान वित्तीय वर्ष 2023 में महामारी पूर्व की स्थिति में 5 प्रतिशत पहुंच गया है।

कृषि और खाद्य प्रबंधन: भविष्य की संभावना का क्षेत्र

1. कृषि और इससे संबंधित क्षेत्रों ने वित्त वर्ष 2024 के (प्रारंभिक अनुमानों) में मौजूदा आधार पर सकल घरेलू उत्पाद में 16 प्रतिशत का योगदान रहा है।
2. वर्ष 2024 में खरीफ खाद्यान्न उत्पादन 1647.05 लाख मीट्रिक टन (एलएमटी) तक पहुंचने की उम्मीद है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 89.37 एलएमटी की वृद्धि दर्शाती है।
3. वित्त वर्ष 2024-25 के लिए अरहर और बाजरा के एमएसपी में उत्पादन की भारित औसत लागत पर क्रमशः 59 प्रतिशत और 77 प्रतिशत की वृद्धि की गई है।
4. 31 अक्टूबर तक पीएम किसान के तहत 11 करोड़ से अधिक किसानों को लाभ मिला है, जबकि 23.61 लाख किसान पीएम किसान मानधन के तहत नामांकित हैं।

जलवायु और पर्यावरण: अनुकूलन की अनिवार्यता

1. वर्ष 2047 तक विकसित राष्ट्र का दर्जा प्राप्त करने की भारत की महत्वाकांक्षा मूल रूप से समावेशी और सतत विकास के दृष्टिकोण में निहित है।
2. भारत गैर-जीवाश्म ईंधन स्रोतों से 2,13,701 मेगावाट की संस्थापित बिजली उत्पादन क्षमता सफलतापूर्वक स्थापित की है, जो वर्ष 2030 तक 50 प्रतिशत तक पहुंचने के एनडीसी के अद्यतित लक्ष्य की तुलना में 30 नवम्बर, 2024 तक कुल क्षमता का 46.8 प्रतिशत है।
3. भारत के नेतृत्व वाले वैश्विक अभियान, लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट (लाइफ) का उद्देश्य देश के स्थिरता संबंधी प्रयासों को बढ़ाना है।

सामाजिक क्षेत्र: पहुंच का विस्तार करना और सशक्तीकरण को आगे बढ़ाना

1. सरकार का सामाजिक सेवा व्यय (संयुक्त रूप से केंद्र और राज्यों के संबंध में) वित्त वर्ष 21 से वित्त 25 तक 15 प्रतिशत की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर से बढ़ा है।
2. वित्त वर्ष 2015 से वित्त वर्ष 2022 के बीच देश के कुल स्वास्थ्य व्यय में सरकारी स्वास्थ्य व्यय की हिस्सेदारी 29.0 प्रतिशत से बढ़कर 48.0 प्रतिशत हो गई है। इसी अवधि के दौरान कुल स्वास्थ्य व्यय में लोगों द्वारा किए जाने वाले आउट-ऑफ-पॉकेट एक्पेंडिचर की हिस्सेदारी 62.6 प्रतिशत से घटकर 39.4 प्रतिशत हो गई।
3. आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (एबीपीएम-जेएवाई) ने परिवारों के जेब खर्च में उल्लेखनीय कमी लाने में निर्णायक भूमिका निभाई है, जिसके अधीन 1.25 लाख करोड़ रुपये से अधिक की बचत दर्ज की गई है।

रोजगार और कौशल विकास: अस्तित्वगत प्राथमिकताएं

1. बेरोजगारी दर 2017-18 (जुलाई-जून) के 6.0 प्रतिशत की तुलना में घटकर 2023-24 में 3.2 प्रतिशत रह जाने के साथ भारतीय श्रम बाजार के संकेतकों में सुधार हुआ है।
2. 10-24 वर्ष के आयु वर्ग में लगभग 26 प्रतिशत जनसंख्या होने के साथ भारत वैश्विक स्तर पर सबसे युवा राष्ट्रों में से एक के तौर पर विशेष जन सांख्यिकी अवसर के मुहाने पर है।
3. महिला उद्यमशीलता को प्रोत्साहन देते हुए सरकार ने आसान कर्ज, विपणन समर्थन, कौशल विकास और महिला स्टार्ट-अप्स को समर्थन आदि से जुड़ी कई पहलों की शुरुआत की है।
4. डिजिटल अर्थव्यवस्था और नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्रों के विकास से रोजगार सृजन के अवसर बढ़ रहे हैं, जो विकसित भारत के विजन को हासिल करने के लिए आवश्यक हैं।
5. हाल में पेश की गई पीएम-इंटर्नशिप योजना रोजगार सृजन को बढ़ावा देने के लिहाज से परिवर्तनकारी साबित हो रही है।
6. ईपीएफओ के तहत बीते 6 साल में कुल नए पेरोल का आंकड़ा दोगुना हो गया है। इससे औपचारिक रोजगार में मजबूत बढ़ोतरी के संकेत मिलते हैं।

एआई युग में श्रम: संकट या उत्प्रेरक?

1. कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) के डेवलपर नए युग में प्रवेश करने का भरोसा दिलाते हैं, जहां आर्थिक रूप से बहुमूल्य ज्यादातर कार्य स्वचालित होंगे।
2. युवा, सक्रिय और तकनीक के मामले में कुशल जनसंख्या के दोहन के द्वारा भारत में ऐसा कार्यबल तैयार करने की क्षमताएं हैं, जो अपने कार्य निष्पादन और उत्पादकता में सुधार के लिए एआई का उपयोग कर सकता है। ■

मोदी स्टोरी

90 के दशक में अमेरिकी यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की हरित ऊर्जा में रुचि

—कंचन बनर्जी, एनआरआई-यूएसए

श्री नरेन्द्र मोदी 1993 में पहली बार अमेरिका गए थे, तो प्रौद्योगिकी एवं विज्ञान के क्षेत्र में होने वाली प्रगति को लेकर उनकी जिज्ञासा काफी प्रबल थी। श्री मोदी, जो उस समय राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के युवा प्रचारक थे, ने अमेरिका को आकार देने वाले तकनीकी नवाचारों के हर विवरण को आत्मसात् करने का प्रयास किया।

इस यात्रा में श्री मोदी के साथ अमेरिका स्थित स्वास्थ्य सेवा पेशेवर श्री कंचन बनर्जी भी थे। टेक्सास के ह्यूस्टन में अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी 'नासा' की अपनी यात्रा को याद करते हुए उन्होंने बताया कि मैंने श्री मोदी को नासा के वरिष्ठ व्यक्ति श्री कमलेश लालाजी से मिलवाया और उन्हें अंतरिक्ष एवं वैमानिकी के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करने का अवसर मिला। वह श्री मोदी की गहन जिज्ञासा से प्रभावित हुए। श्री बनर्जी याद कर कहते हैं, "वह ऐसे सवाल पूछ रहे थे जैसे वह कोई भौतिक विज्ञानी हों। विज्ञान और अंतरिक्ष के बारे में उनकी समझ उल्लेखनीय थी और उनके सवालों की जटिलता ने मुझे आश्चर्यचकित कर दिया।"

विज्ञान के प्रति उनके आकर्षण के अलावा, इस यात्रा के दौरान श्री मोदी की सादगी और आत्मनिर्भरता की सोच भी स्पष्ट थी। श्री बनर्जी ने बताया कि श्री नरेन्द्र मोदी ने सिर्फ एक छोटा सा बैग लेकर यात्रा की, जिसमें दो जोड़ी कपड़े और एक कैमरा था, जो फोटोग्राफी के प्रति उनके जुनून को दर्शाता है। अन्य लोगों के घर में मेहमान होने के बावजूद श्री मोदी ने कभी भी अपने मेजबानों पर कोई दबाव नहीं डाला। श्री बनर्जी कहते हैं, "जब मेरी पत्नी ने उनके कपड़े धोने का आग्रह किया, तो उन्होंने विनम्रतापूर्वक मना कर दिया और जोर देकर कहा कि वह स्वयं ही कपड़े धो लेंगे। एक प्रचारक के तौर पर आत्मनिर्भरता की भावना उनके चरित्र का एक मुख्य हिस्सा थी।"

अपनी यात्राओं के दौरान श्री नरेन्द्र मोदी ने सौर एवं हरित ऊर्जा को लेकर भी अपनी रुचि दिखाई। बोस्टन में वैज्ञानिकों के साथ चर्चा के दौरान उन्होंने खेती योग्य भूमि पर सौर पैनल लगाने के मुद्दे पर सबका ध्यान आकर्षित किया, उन्होंने कहा कि ऐसा करने से खेती योग्य भूमि अनुपयोगी हो जाती है। श्री मोदी ने सिंचाई नहरों पर सौर पैनल लगाने का सुझाव दिया, जिससे भूमि की बचत होगी और नहरों से पानी का वाष्पीकरण भी कम होगा। इस विचार को बाद में भारत में लागू किया गया, जिससे सतत विकास को लेकर उनकी दूरदर्शिता का पता चलता है।

श्री मोदी ने बोस्टन की अपनी यात्रा के दौरान पहली बार स्वचालित टोल बूथ भी देखे और मानवीय भूल को खत्म करने एवं भ्रष्टाचार से निपटने की उनकी क्षमता को पहचाना। उन्होंने जल्दी ही समझ लिया कि इन नवाचारों को भारत में कैसे अपनाया जा सकता है, इसके लिए केवल नकल करने की अवश्यकता नहीं थी, बल्कि देश की जरूरतों के हिसाब से उन्हें लागू किया जाना था।

श्री कंचन बनर्जी याद करते हैं कि श्री नरेन्द्र मोदी की न्यूयॉर्क, शिकागो और अटलांटा सहित प्रमुख अमेरिकी शहरों की यात्राओं ने उन पर गहरा प्रभाव डाला। श्री बनर्जी कहते हैं, "मुझे यकीन है कि उस समय भारत की गरीबी और पिछड़ेपन को देखकर उन्हें दुःख हुआ होगा। श्री मोदी के अनुभव ने संभवतः विकास पर उनका ध्यान केंद्रित किया, यह समझते हुए कि लोगों को गरीबी से बाहर निकालने के लिए बुनियादी जीवन स्तर में सुधार करना आवश्यक था।" ■

कमल पुष्प

सेवा, समर्पण, त्याग, संघर्ष एवं बलिदान

विश्वनाथ राय

बिहार निवासी श्री विश्वनाथ राय अपने शुरुआती जीवन में ही भारतीय जनसंघ से जुड़ गये थे। उन्होंने 1974 के जेपी आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई और 1975 के आपातकाल के दौरान जेल भी गए थे। 1980 में उन्होंने भाजपा के टिकट पर राजपुर (सु.) से चुनाव लड़ा और 1985 में राजपुर (सु.) से विधायक बने। लंबे समय तक संगठन की सेवा करने के बाद 24 जुलाई, 2016 को उनका स्वर्गवास हो गया। ■

सुशासन के सच्चे पथ प्रदर्शक 'भारत रत्न' अटल बिहारी वाजपेयी

राजकुमार चाहर

देश के पूर्व प्रधानमंत्री 'भारत रत्न' श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी प्रखर वक्ता, कवि, राजनेता, कुशल लेखक, पत्रकार, स्वतंत्रता सेनानी और न जानें कितने दुर्लभ प्रतिभा के धनी थे। अटल बिहारी वाजपेयी नाम तो एक, लेकिन शख्सियत ऐसी कि मानो सभी गुण उन्हीं में समाहित हों। उनके मिलनसार स्वभाव के कारण ही लोग हमेशा उनके कायल रहे। भारत के लिए उनकी स्मृतियां जितनी अनमोल हैं, उतनी ही महत्वपूर्ण हैं उनसे जुड़ी हर जगह, जिससे उनको लगाव था। भारत माता के प्रति अटल जी का समर्पण और प्रतिबद्धता बहुत ही अलौकिक है, उनका व्यक्तित्व आज भी हम सभी को प्रेरणा देने का कार्य करता है।

बटेश्वर के रहने वाले थे अटल जी

मैंने 22 जुलाई, 2024 को लोकसभा के अंदर 377 के अधीन अटल जी की जनस्थली बटेश्वर में विशाल प्रतिमा बनवाने का आग्रह किया था जिसको मोदी सरकार ने स्वीकृति दे दी है। बहुत जल्द बटेश्वर में अटल जी की विशाल एवं अकल्पनीय 65 फुट ऊंची भव्य प्रतिमा बनकर तैयार होगी। इससे पूर्व भी मोदी सरकार ने बटेश्वर को विश्व स्तरीय पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने के लिए 74 करोड़ रुपए की विशेष परियोजना को मंजूरी दी, जिसके लिए यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी एवं मंत्री श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत जी के प्रति विशेष आभार व्यक्त करता हूं।

अटल जी के पैतृक गांव बटेश्वर जो फ़तेहपुर सीकरी लोकसभा में आता है। यह मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात हैं की लगातार दूसरी बार मुझे सांसद के रूप में इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। आगरा से सटा बटेश्वर धाम, शिव मंदिरों की श्रृंखला से सुसज्जित ये धरा पूर्व प्रधानमंत्री अटल जी का पैतृक गांव भी है। तीर्थों का भांजा कहे जाने वाले बटेश्वर धाम भारत के बहुत ही प्रसिद्ध स्थानों में से एक हैं। अटल जी मूल रूप से बटेश्वर के रहने वाले थे। इस जगह को भूतेश्वर नाम से भी जाना जाता है। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार बटेश्वर को तीर्थों का भांजा कहा जाता है।

> अटलजी ने किसानों को साहूकारों के चंगुल से मुक्त कराने के लिए किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा उपलब्ध कराई, गेहूं के समर्थन मूल्य में 19.6 प्रतिशत बढ़ोतरी कराई, चीनी मिलों को लाइसेंस प्रणाली से मुक्ति और राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना तैयार कराई

वाजपेयी जी राजनीति के क्षेत्र में 5 दशकों तक सक्रिय रहे। वे लोकसभा में 9 बार और राज्यसभा में 2 बार चुने गए और एक कीर्तिमान स्थापित किया। वे 1980 में गठित भाजपा के संस्थापक अध्यक्ष भी रहे। उन्होंने 13 अक्टूबर, 1999 को लगातार तीसरी बार राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार के प्रमुख के रूप में भारत के प्रधानमंत्री का पद ग्रहण किया और कार्यकाल पूर्ण किया। इससे पहले वे 1996 में 13 दिन और 1998 में 13 महीने के लिए दो बार प्रधानमंत्री रह चुके थे। इसके अलावा विदेश मंत्री, संसद की विभिन्न महत्वपूर्ण स्थायी समितियों के अध्यक्ष और विपक्ष के नेता के रूप में उन्होंने आजादी के बाद भारत की घरेलू और विदेश नीति को आकार देने में एक सक्रिय भूमिका निभाई। वे अपनी राजनीतिक प्रतिबद्धता के लिए जाने जाते हैं।

गांव से थे इसलिए किसानों की पीड़ा को समझते थे

अटल बिहारी वाजपेयी जी किसानों की पीड़ा को समझते थे। जब देश के प्रधानमंत्री बने तो सबसे पहले किसानों के हक में ऐतिहासिक फैसले लिए। किसानों को साहूकारों के चंगुल से मुक्त कराने के लिए किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा उपलब्ध कराई, गेहूं के समर्थन मूल्य 19.6 प्रतिशत बढ़ोतरी कराई, चीनी मिलों को लाइसेंस प्रणाली से मुक्ति और राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना तैयार कराई। किसानों को सिंचाई के लिए पर्याप्त जल मिले, इसके लिए नदियों को आपस में जोड़ने की योजना लाए। किसान की उपज अन्य प्रांतों में भी पहुंचे, उसके लिए उन्होंने उच्चस्तरीय सड़कों की कनेक्टिविटी पर कार्य किया। इतना ही नहीं अटल बिहारी वाजपेयी 15 अगस्त 2003 को जब लाल किले के प्राचीर से देश को संबोधित कर रहे थे, तब पहली बार उन्होंने ही किसानों की आय दोगुना करने की बात कही थी।

गांव, गरीब के लिए ऐतिहासिक फैसले

वाजपेयी जी के कार्यकाल में ही 6 से 14 वर्ष के बच्चों को मुफ्त शिक्षा देने का अभियान शुरू किया गया था, जिसे उन्होंने सन् 2000-01 में सर्व शिक्षा अभियान स्कीम को लागू करके पैसे के अभाव से पढ़ाई छोड़ देने वाले बच्चों को फायदा पहुंचाया तथा 'स्कूल चले हम' थीम की लाइन लिखकर प्रमोट किया। इस तरह 'सर्व शिक्षा अभियान' को बढ़ावा मिला।

इन सबके अलावा अटल बिहारी वाजपेयी ने सड़कों के माध्यम से भारत को जोड़ने की योजना बनाई थी, जिसमें उन्होंने प्रमुख रूप से चेन्नई, कोलकाता, दिल्ली और मुंबई को जोड़ने के लिए स्वर्णिम चतुर्भुज सड़क परियोजना लागू की, साथ ही ग्रामीण सड़क योजना के उनके फैसले ने देश के ग्रामीण और आर्थिक विकास को बढ़ावा दिया, जिसे भारतीय राजनीति में सबसे ज्यादा अहम कार्य माना जा सकता है।

प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना

गांवों को जोड़ने वाली प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना की पक्की सड़कों ने तो गांवों की तस्वीर बदल दी। अटल बिहारी वाजपेयी जी ग्रामीण क्षेत्रों में कनेक्टिविटी के अभाव को सबसे बड़ी समस्या मानते थे। 70 फीसदी आबादी वाले ग्रामीण क्षेत्रों के लिए उनके एक क्रांतिकारी फैसले से ग्रामीण भारत की तकदीर बदल गई। उन्होंने गांवों को सड़क से जोड़ने का काम शुरू किया। उन्हीं के कार्यकाल के दौरान दिसंबर, 2000 में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना की शुरुआत हुई थी। फिलहाल प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से देश के 90 फीसदी से ज्यादा गांव सड़क से जुड़ चुके हैं। अटल जी की चलाई यह योजना आज भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। शहरों से सीधे जुड़ाव हो जाने से गांव में रहने वाले लोगों की जिंदगी बदल गई। कृषि उपज को मंडियों तक ले जाने और रोजी-रोजगार के रास्ते आसान हुए। पक्की सड़क हो जाने से गांव तक लोगों के लिए शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी मूलभूत जरूरतें आसानी से मुहैया हो रही हैं।

गांवों का संपूर्ण विकास 'प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना'

अटल बिहारी वाजपेयी जी गांवों में रहने वाले लोगों के जीवन स्तर में सुधार को लेकर हमेशा प्रयासरत रहे। इसी मकसद से 2000-2001 में उनकी सरकार ने प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना की शुरुआत की। इसके जरिए गांव में रहने वाले लोगों को शुरुआती शिक्षा, बेहतर सड़कें, पीने के लिए साफ पानी, बुनियादी स्वास्थ्य सेवाएं और पोषण मुहैया कराने का लक्ष्य रखा गया। बाद में इसमें बिजली मुहैया कराने का भी लक्ष्य जोड़ दिया गया। इस योजना का मुख्य मकसद ग्रामीण इलाकों में गरीबी दूर कर लोगों के जीवन को बेहतर बनाना था।

संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना

ग्रामीण भारत के गरीबों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए अटल बिहारी वाजपेयी जी ने 25 सितंबर, 2001 को संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना की शुरुआत की। इसके लिए 10,000 करोड़ रुपए सालाना का बजट भी निर्धारित किया गया था। योजना के लाभार्थियों को प्रतिदिन की मजदूरी के हिसाब 40 रुपए या 8 किलो गेहूं दिया जाता था।

गरीबों के लिए अंत्योदय अन्न योजना

अंत्योदय अन्न योजना देश के गरीबों के लिए वाजपेयी सरकार की ओर से चलाई गई सबसे बड़ी योजना थी। 25 दिसंबर, 2000 को इस योजना की शुरुआत की गई। इस योजना के तहत गरीबों में भी ज्यादा गरीब लोगों को रियायती दर पर गेहूं और चावल उपलब्ध करवाने की व्यवस्था की गई। इसके तहत 1 करोड़ परिवारों को 2 रुपये प्रति किलो की दर से गेहूं और तीन रुपये प्रति किलो की दर पर चावल उपलब्ध करवाना था। इसके बाद 2003 में इस योजना को बढ़ाया गया और 50 लाख परिवार और जोड़ दिए गए। 2004 में योजना एक बार फिर से बढ़ाई गई और फिर से 50 लाख परिवारों को जोड़ा गया। कुल मिलाकर इस योजना के तहत 2 करोड़ परिवारों को सस्ती कीमत पर राशन मुहैया करवाने की व्यवस्था की गई। इन परिवारों की पहचान के लिए वाजपेयी सरकार ने पूरे देश में व्यापक स्तर पर सर्वे करवाए थे और उनके लिए राशन कार्ड बनवाए थे। इतना सस्ता अनाज पहले कभी नहीं दिया गया। ये दुनिया की सबसे बड़ी खाद्य सुरक्षा योजना थी। अटल जी 'मां भारती' के सच्चे सपूत होने के साथ ही साथ उनका संपूर्ण जीवन देश के विकास और गांव खेत किसान की प्रगति के लिए पूरी तरह से समर्पित था, उनके द्वारा राष्ट्र के कल्याण व उत्थान के हित में लिए गए फ़ैसले बहुत ही ऐतिहासिक और अभूतपूर्व थे, अटल जी का आदर्शपूर्ण जीवन सदैव ही हम सभी करोड़ों करोड़ कार्यकर्ताओं को प्रेरणा देता रहेगा। ■

(लेखक भाजपा किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं सांसद हैं)

बजट सत्र 2025 : राष्ट्रपति अभिभाषण

आज देश बड़े निर्णयों और नीतियों को असाधारण गति से लागू होते देख रहा है: राष्ट्रपति

भारत की राष्ट्रपति माननीय श्रीमती द्रौपदी मुर्मु ने बजट सत्र के प्रथम दिन 31 जनवरी, 2025 को संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि अभी दो माह पहले हमने संविधान को अपनाने की 75वीं वर्षगांठ मनाई है और कुछ दिन पहले ही भारतीय गणतंत्र ने 75 वर्षों की यात्रा भी पूरी की है। ये अवसर लोकतन्त्र की जननी के रूप में भारत के गौरव को नयी उंचाई देगा। श्रीमती मुर्मु ने सभी देशवासियों की तरफ से बाबासाहेब अंबेडकर समेत सभी संविधान निर्माताओं को नमन किया। यहां प्रस्तुत है उनके संबोधन के प्रमुख अंशः

- भारत की विकास यात्रा के इस अमृतकाल को आज मेरी सरकार अभूतपूर्व उपलब्धियों के माध्यम से नई ऊर्जा दे रही है। तीसरे कार्यकाल में तीन गुना तेज गति से काम हो रहा है। आज देश बड़े निर्णयों और नीतियों को असाधारण गति से लागू होते देख रहा है और इन निर्णयों में देश के गरीब, मध्यम वर्ग, युवा, महिलाओं, किसानों को सर्वोच्च प्राथमिकता मिली है।
- मेरी सरकार गांव में गरीबों को उनकी आवासीय भूमि का हक़ देने और वित्तीय समावेशन के लिए प्रतिबद्ध है। इस दिशा में स्वामित्व योजना के अंतर्गत अब तक दो करोड़ पच्चीस लाख सम्पत्ति कार्ड जारी किए हैं। इनमें से करीब 70 लाख स्वामित्व कार्ड पिछले 6 महीने में जारी हुए हैं।
- जनजातीय समाज के पांच करोड़ लोगों के लिए 'धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष' अभियान प्रारंभ हुआ है। इसके लिए अस्सी हज़ार करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
- आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत सत्तर वर्ष और उससे अधिक उम्र के छह करोड़ वरिष्ठ नागरिकों को स्वास्थ्य बीमा देने का फैसला हुआ है। इन्हें हर वर्ष पांच लाख रुपये का हेल्थ कवर मिलेगा।
- सरकार ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के चौथे चरण में पच्चीस हज़ार बस्तियों को जोड़ने के लिए सत्तर हज़ार करोड़ रुपए स्वीकृत किए हैं। आज जब हमारा देश अटल जी की जन्म शताब्दी का वर्ष मना रहा है, तब प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना उनके विजन का पर्याय बनी हुई है।

'वन नेशन-वन इलेक्शन'

- 'वन नेशन-वन इलेक्शन' और 'वक्फ़ अधिनियम संशोधन' जैसे कई महत्वपूर्ण विषयों पर भी सरकार ने तेज गति से कदम आगे बढ़ाए हैं।
- उड़ान योजना ने लगभग डेढ़ करोड़ लोगों का हवाई जहाज में उड़ने का सपना पूरा किया है। जन औषधि केंद्र में 80 प्रतिशत रियायती दरों पर मिल रही दवाओं से देशवासियों के 30 हजार करोड़ रुपए से ज्यादा बचे हैं। हर विषय की पढ़ाई के लिए सीटों की संख्या में कई गुना बढ़ोतरी का बहुत लाभ मध्यम वर्ग को मिला है।
- राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत इक्यानवे लाख से अधिक स्वयं सहायता समूहों को सशक्त किया जा रहा है। देश की दस करोड़ से भी अधिक महिलाओं को इसके साथ जोड़ा गया है। इन्हें कुल नौ लाख करोड़ रुपये से अधिक की राशि बैंक लिंकेज के माध्यम से वितरित की गई है।
- यह इस संसद के लिए गौरव का विषय है कि बड़ी संख्या में भारत की बेटियां लड़ाकू विमान उड़ा रही हैं, पुलिस में भर्ती हो रही हैं और कॉरपोरेट कंपनियों का नेतृत्व भी कर रही हैं। मेरी सरकार के निर्णय के बाद बालिकाओं की भर्ती राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूलों में प्रारंभ हो गई है। नेशनल डिफेंस अकैडमी में भी महिला कैडेट्स की भर्ती शुरू हो गई है।
- पिछले एक दशक में मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड-अप इंडिया और डिजिटल इंडिया जैसी पहल ने युवाओं को रोज़गार के अनेक अवसर प्रदान किए हैं। पिछले दो वर्षों में सरकार ने रिकॉर्ड संख्या में दस लाख स्थायी सरकारी नौकरियां प्रदान की हैं।
- मेरी सरकार ने युवाओं के बेहतर कौशल और नए अवसरों के सृजन के लिए दो लाख करोड़ रुपए का पैकेज स्वीकृत किया है।
- क्यूएस वर्ल्ड फ्यूचर स्किल इंडेक्स 2025 में भारत विश्व में दूसरे नंबर पर पहुंच गया है। यानी फ्यूचर ऑफ वर्क श्रेणी में AI और डिजिटल तकनीक अपनाने में भारत दुनिया को रास्ता दिखा रहा है।
- ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भी भारत की रैंकिंग 76 से सुधर कर 39 हो गई है।

विद्यार्थियों के लिए आधुनिक शिक्षा व्यवस्था

- मेरी सरकार राष्ट्रीय शिक्षा नीति के माध्यम से विद्यार्थियों के लिए आधुनिक शिक्षा व्यवस्था तैयार कर रही है। कोई भी शिक्षा से वंचित न रहे, इसीलिए मातृ भाषा में शिक्षा के अवसर दिये जा रहे हैं। विभिन्न भर्ती परीक्षाएं तेरह भारतीय भाषाओं में आयोजित कर भाषा संबंधी बाधाओं को भी दूर किया गया है।
- कुछ ही दिन पहले इसरो ने अपना सौवां लॉन्च करते हुये सैटेलाइट

को सफलतापूर्वक स्थापित किया है। मैं इस उपलब्धि के लिए भी इसरो को और सभी देशवासियों को बधाई देती हूं।

- दस हज़ार करोड़ रुपए की लागत से 'विज्ञानधारा योजना' के तहत विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में इनोवेशन को बढ़ावा दिया जा रहा है।
- तीसरे कार्यकाल में मेरी सरकार द्वारा मुद्रा ऋण की सीमा को दस लाख रुपए से बढ़ाकर बीस लाख रुपए करने का लाभ करोड़ों छोटे उद्यमियों को हुआ है।
- ओएनडीसी की व्यवस्था ने डिजिटल कॉमर्स यानी ऑनलाइन शॉपिंग की व्यवस्था को समावेशी बनाया है। आज देश में छोटे बिजनेस को भी आगे बढ़ने का समान अवसर मिल रहा है।
- भारत की यूपीआई टेक्नॉलाजी की सफलता से दुनिया के कई विकसित देश भी प्रभावित हैं। आज 50 प्रतिशत से ज्यादा रियल टाइम डिजिटल ट्रांजैक्शन भारत में हो रहा है।
- दस साल पहले बुनियादी ढांचे का बजट लगभग दो लाख करोड़ रुपये था, जो पिछले बजट में बढ़कर ग्यारह लाख करोड़ रुपये से अधिक हो गया।
- भारत का एविएशन सेक्टर तेज़ी से विकास कर रहा है। देश की एयरलाइन कम्पनियों ने सत्रह सौ से अधिक नए विमानों के ऑर्डर दिए हैं। इतनी बड़ी संख्या में आने वाले विमानों के परिचालन के लिए हम एयरपोर्ट्स का विस्तार कर रहे हैं। पिछले एक दशक में देश में एयरपोर्ट्स की संख्या दोगुनी हो गई है।

देश भर में बारह इंडस्ट्रिअल नोड

- मेरी सरकार ने लगभग अठ्ठाइस हज़ार करोड़ रुपए के निवेश से देश भर में बारह इंडस्ट्रिअल नोड और शहरों के पास सौ औद्योगिक पार्क बनाने का भी निर्णय लिया है।
- भारत का मेट्रो नेटवर्क अब एक हज़ार किलोमीटर के माइलस्टोन को पार कर चुका है। भारत अब मेट्रो नेटवर्क के मामले में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा देश बन गया है।
- सरकार हेल्थ इन्फ्रास्ट्रक्चर और मेडिकल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा दे रही है। देश में नए बल्क ड्रग और मेडिकल डिवाइसेस के पार्क भी बनाए जा रहे हैं। इनमें रोजगार के अनेक नए अवसर उपलब्ध हो रहे हैं।

रिकॉर्ड तीन सौ बत्तीस मिलियन टन अनाज उत्पादन

- वर्ष 2023-24 में रिकॉर्ड तीन सौ बत्तीस मिलियन टन अनाज उत्पादन हुआ है और आज भारत विश्व का सबसे बड़ा दूध, दाल और मसालों का उत्पादक है।
- बाबासाहेब अंबेडकर के विजन पर चलते हुए देश के सूखाग्रस्त इलाकों में सिंचाई और पीने का पानी उपलब्ध कराने के लिए मेरी सरकार ने दो ऐतिहासिक रिवर इंटरलिंकिंग परियोजनाओं पर काम आगे बढ़ाया है। 44,000 करोड़ रुपये से अधिक लागत की केन-बेतवा लिंक परियोजना से मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के लाखों ग्रामीण भाई-बहनों को लाभ मिलेगा।
- देश भर में स्थापित चार सौ सत्तर से अधिक एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों के माध्यम से लगभग सवा लाख आदिवासी बच्चों को स्कूली शिक्षा दी जा रही है। पिछले दस वर्षों में आदिवासी बहुल इलाकों में तीस नए मेडिकल कॉलेज खोले गए हैं।
- मेरी सरकार ने नॉर्थ-ईस्ट के लोगों की इन्हीं भावनाओं को समझा, उनके दिल से दूरियों का भाव समाप्त किया। दस से अधिक शांति समझौते कर सरकार ने अनेक गुटों को शांति के मार्ग से जोड़ने का काम किया है।
- देश की विरासत का एक महत्वपूर्ण स्तंभ हमारी समृद्ध भाषा-संस्कृति है। मुझे खुशी है कि सरकार ने असमी, मराठी, पाली, प्राकृत और बांग्ला भाषाओं को क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा दिया है।

1500 से अधिक पुराने अनावश्यक कानून निरस्त

- सरकार अब तक 1500 से अधिक पुराने अनावश्यक कानूनों को निरस्त कर चुकी है। गुलामी के कानूनों को हटाकर दंड संहिता के स्थान पर न्याय संहिता लागू की गई है।
- कुछ दिन पहले एक ऐतिहासिक पल में देश में बने दो युद्धपोतों और एक पनडुब्बी को भारतीय नौसेना में कमीशन किया गया है। देश में डिफेन्स इंडस्ट्रिअल कॉरीडोर की स्थापना और डिफेन्स स्टार्टअप्स को प्रोत्साहन देकर हम आत्मनिर्भरता और स्वरोजगार को मजबूती दे रहे हैं।
- वामपंथी उग्रवाद को समाप्त करने के अंतिम चरण की भी शुरुआत हो चुकी है। सरकार के प्रयासों से वामपंथी-उग्रवाद प्रभावित जिलों की संख्या 126 से घटकर अब 38 तक आ गई है।
- वैश्विक अस्थिरता के वातावरण में भारत आर्थिक, सामाजिक और राजनैतिक स्थिरता का स्तम्भ बनकर विश्व के सामने आदर्श प्रस्तुत कर रहा है। चाहे जी-7 समिट हो, क्वाड, ब्रिक्स, एससीओ हो या जी-20, भारत के सामर्थ्य, नीति और नीयत पर पूरे विश्व ने भरोसा जताया है।
- मेरी सरकार वर्तमान के साथ ही आने वाली पीढ़ियों को ध्यान में रखते हुए भी निर्णय ले रही है। हम देश को ग्रीन फ्यूचर, ग्रीन जॉब्स की तरफ ले जा रहे हैं।
- आने वाले वर्षों में देश को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए हम सभी दृढ़ संकल्पित हैं। इस संकल्प में देश के शहीदों की प्रेरणाएं हैं, पूज्य बापू के मानवीय आदर्श हैं और सरदार पटेल जैसी मां भारती की संतानों द्वारा हमें दिलाई गई एकता की शपथ है। हमें इन प्रेरणाओं को आगे रखते हुये एकता के इस सामर्थ्य से विकसित भारत के संकल्प को पूर्ण करना है। ■

प्रधानमंत्री का लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर हुई चर्चा का उत्तर

आदरणीय राष्ट्रपति जी का उद्बोधन 'विकसित भारत' के संकल्प को मजबूती देने वाला है: नरेन्द्र मोदी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने चार फरवरी को लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर हुई चर्चा का जवाब दिया। सदन को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने चर्चा में भाग लेने वाले सभी माननीय सांसदों के योगदान की सराहना की और कहा कि लोकतंत्र की परंपरा में जहां आवश्यक हो वहां प्रशंसा और जहां आवश्यक हो वहां कुछ नकारात्मक टिप्पणियां दोनों ही शामिल हैं, जो स्वाभाविक है। यहां प्रस्तुत है श्री मोदी के संबोधन की मुख्य बातें:

- आदरणीय राष्ट्रपति जी का यह उद्बोधन 'विकसित भारत' के संकल्प को मजबूती देने वाला है, नया विश्वास पैदा करने वाला है और जन सामान्य को प्रेरित करने वाला है।
- गत 10 वर्ष में देश की जनता ने हमें सेवा करने का मौका दिया। 25 करोड़ देशवासी गरीबी को परास्त कर इससे बाहर निकले हैं।
- अब तक गरीबों को 4 करोड़ घर मिले हैं। जिसने उस जिंदगी को जिया है ना, उसे समझ होती है कि पक्की छत वाला घर मिलने का मतलब क्या होता है।
- हमने 12 करोड़ से ज्यादा शौचालय बनाकर बहनों-बेटियों की मुश्किलें दूर की हैं।
- आजादी के 75 साल के बाद देश में 70-75% करीब-करीब 16 करोड़ से भी ज्यादा घरों के पास जल के लिए, नल का कलेक्शन नहीं था। हमारी सरकार ने 5 साल में 12 करोड़ परिवारों को घरों में नल से जल देने का काम किया है।

हमारा मॉडल है 'बचत भी विकास भी' जनता का पैसा जनता के लिए

- हमारा मॉडल है 'बचत भी विकास भी', जनता का पैसा जनता के लिए। हमने जनधन आधार मोबाइल की जेम ट्रिनिटी बनाई और डीबीटी से डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर देना शुरू किया। हमारे कार्यकाल में हमने 40 लाख करोड़ रुपया सीधा जनता जनार्दन के खाते में जमा किया।
- इंफ्रास्ट्रक्चर का बजट 10 साल पहले 1,80,000 करोड़ रुपए था। आज 11 लाख करोड़ रुपया इंफ्रास्ट्रक्चर का बजट है।
- आयुष्मान भारत योजना ने लोगों के लगभग 1.2 लाख करोड़ रुपए बचाए हैं।
- यूनिसेफ का भी अनुमान है कि जिसके घर में स्वच्छता और टॉयलेट बना है, उस परिवार को करीब-करीब साल भर में 70,000 रुपये की बचत हुई है।
- WHO की एक रिपोर्ट आई है, WHO का कहना है की नल से जल शुद्ध पानी मिलने के कारण उन परिवारों में जो अन्य बीमारियों के खर्चे होते थे, औसत 40,000 रुपया बचा है।
- पीएम सूर्यगढ़ मुफ्त बिजली योजना ने परिवारों की बिजली खर्च पर सालाना औसतन 25,000 रुपए से 30,000 रुपए की बचत की है।
- जिन किसानों ने सॉइल हेल्थ कार्ड का वैज्ञानिक तरीके से उपयोग किया है, उनको बहुत फायदा हुआ है और ऐसे किसानों को प्रति एकड़ 30,000 रुपये की बचत हुई है।

मध्यम वर्ग की बचत में वृद्धि

- पिछले दस वर्षों में सरकार ने आयकर की दरों को कम किया है, जिससे मध्यम वर्ग की बचत में वृद्धि हुई है।
- 2013-14 में केवल 2 लाख रुपये आयकर से मुक्त थे, जबकि आज 12 लाख रुपये पूरी तरह से आयकर से मुक्त हैं।
- 2014, 2017, 2019 और 2023 के दौरान सरकार ने लगातार राहत प्रदान करने पर काम किया है और 75,000 रुपये की मानक कटौती के साथ वेतनभोगी व्यक्तियों को 1 अप्रैल से 12.75 लाख रुपये तक की आय पर कोई आयकर नहीं देना होगा।
- भारत के एआई मिशन ने वैश्विक आशावाद पैदा किया है और विश्व एआई मंच पर भारत की उपस्थिति महत्वपूर्ण हो गई है।
- जब सत्ता सेवा बन जाए, तो राष्ट्र निर्माण होता है। जब सत्ता को विरासत बना दिया जाए, तब लोकतंत्र खत्म हो जाता है।
- हम संविधान की भावना को लेकर के चलते हैं। हम जहर की राजनीति नहीं करते। हम देश की एकता को सर्वोपरि रखते हैं और इसलिए सरदार वल्लभभाई पटेल का दुनिया का सबसे ऊंचा स्टैच्यू बनाते हैं और देश को जोड़ने का जिस महापुरुष ने काम किया, उसका हम स्मरण करते हैं और वो भाजपा के नहीं थे, वो जनसंघ के

नहीं थे। हम संविधान को जीते हैं, इसलिए इस सोच से आगे बढ़ते हैं।

हम संविधान की भावना को जीते हैं

- सात दशक तक जम्मू-कश्मीर और लद्दाख को संविधान के अधिकारों से वंचित रखा गया। यह संविधान के साथ भी अन्याय था और जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के लोगों के साथ भी अन्याय था। हमने आर्टिकल 370 की दीवार गिरा दी, अब जम्मू-कश्मीर और लद्दाख को; देशवासियों को जो अधिकार हैं, वो अधिकार उनको मिल रहे हैं और संविधान का महात्मय हम जानते हैं, संविधान की भावना को जीते हैं, इसलिए ऐसे मजबूत निर्णय भी हम करते हैं।
- पिछले 30 साल से सदन में आने वाले ओबीसी समाज के सांसद, दलों के भेदभाव से ऊपर उठकर के एक हो करके 30-35 साल से मांग कर रहे थे कि ओबीसी कमीशन को संवैधानिक दर्जा दिया जाए। जिन लोगों को आज जातिवाद में मलाई दिखती है, उनको उस समय ओबीसी समाज की याद नहीं आई, यह हम हैं जिन्होंने ओबीसी समाज को संवैधानिक दर्जा दिया। पिछड़ा वर्ग आयोग आज संवैधानिक व्यवस्था में जुड़ा है।
- 2014 से पहले हमारे देश में मेडिकल कॉलेज की संख्या 387 थी। आज 780 मेडिकल कॉलेज हैं। अब मेडिकल कॉलेज बढ़े हैं तो सीटें भी बढ़ी हैं।
- 2014 से पहले हमारे देश में एससी छात्रों की एमबीबीएस की सीट 7700 थी। हमारे आने से पहले दलित समाज के हमारे 7700 युवा डॉक्टर बनने की संभावना थी। 10 साल हमने काम किया, आज संख्या बढ़कर एससी समाज के 17,000 एमबीबीएस डॉक्टर की व्यवस्था की है।
- 2014 के पहले एसटी छात्रों के लिए एमबीबीएस की सीटें 3800 थीं। आज यह संख्या बढ़कर लगभग 9,000 हो गई है। 2014 के पहले ओबीसी के छात्रों के लिए एमबीबीएस में 14,000 से भी कम सीटें थी। आज इनकी संख्या लगभग 32,000 हो गई है। ओबीसी समाज के 32,000 एमबीबीएस डॉक्टर बनेंगे।
- आज आयुष्मान से देश के 30,000 अस्पताल जुड़े हैं और अच्छे स्पेशलाइज्ड प्राइवेट अस्पताल जुड़े हैं। जहां आयुष्मान कार्ड वाले को मुफ्त इलाज मिलता है।
- इस बजट में भी हमने कैंसर की दवाइयों को सस्ती करने की दिशा में बहुत बड़ा महत्वपूर्ण कदम उठाया है।

वीमेन लेड डेवलपमेंट

- आज भारत 'वीमेन लेड डेवलपमेंट' के मंत्र को लेकर के आगे बढ़ रहा है। अगर आधी आबादी को पूरा अवसर मिले, तो भारत दो गुनी रफ्तार से आगे बढ़ सकता है।
- पिछले 10 साल में सेल्फ हेल्प ग्रुप्स में अब तक 10 करोड़ नई महिलाएं जुड़ी हैं और ये महिलाएं वंचित परिवारों से हैं, ग्रामीण बैकग्राउंड से हैं। समाज के अंतिम पायदान पर बैठी इन महिलाओं का सामर्थ्य बढ़ा, उनका सामाजिक स्तर भी ऊपर उठा और सरकार ने इनकी मदद 20 लाख रुपए तक बढ़ा दी है, ताकि वो इस काम को आगे बढ़ा सकें।
- 'विकसित भारत' के 4 स्तंभों में हमारा किसान एक मजबूत स्तंभ है। बीते दशक में खेती के बजट में 10 गुना वृद्धि की गई है।
- आज भारत सरकार को जो बोरा यूरिया का 3,000 रुपये में पड़ता है, सरकार ने बोझ झेला और किसान को 300 रुपये से भी कम कीमत पर दिया है।

सस्ती खाद हेतु पिछले 10 साल में 12 लाख करोड़ रुपया खर्च

- किसानों को सस्ती खाद मिले इस एक काम के लिए पिछले 10 साल में 12 लाख करोड़ रुपया खर्च किया गया है। पीएम किसान सम्मान निधि, उससे करीब साढ़े तीन लाख करोड़ रुपए डायरेक्ट किसान के खाते में पहुंचे हैं। हमने रिकॉर्ड एमएसपी भी बढ़ाया और पहले की तुलना में बीते दशक में तीन गुना अधिक खरीदी की है।
- किसान को ऋण मिले, आसान ऋण मिले, सस्ता ऋण मिले, उसमें भी तीन गुना वृद्धि की गई है। पहले प्राकृतिक आपदा में किसान को अपने हाल पर छोड़ दिया जाता था। हमारे सेवाकाल के दौरान पीएम फसल बीमा के तहत 2 लाख करोड़ रुपए किसानों को मिले हैं।

मिशन मैन्युफैक्चरिंग पर बल

- इस बार हमने मिशन मैन्युफैक्चरिंग पर बल दिया है और एक मिशन मोड में हम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर; मतलब की MSMEs को बल देना और MSMEs के माध्यम से अनेक नौजवानों को रोजगार देना और स्किल डेवलपमेंट से रोजगार के लिए नौजवानों को तैयार करना, ऐसे पूरे इकोसिस्टम को हम बल देते हुए आगे बढ़ रहे हैं।
- 2014 के पहले खिलौने जैसे चीजें हम इंपोर्ट करते थे, आज मैं गर्व से कह सकता हूं कि मेरे देश के खिलौने बनाने वाले छोटे उद्योग, आज दुनिया के अंदर खिलौने एक्सपोर्ट हो रहे हैं और आयात में बहुत बड़ी गिरावट आई है। निर्यात में करीब 239 परसेंट वृद्धि हुई है।
- 'विकसित भारत' के सपने को पूरा करने के लिए देश आगे बढ़ रहा है और बड़े आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ रहा है। विकसित भारत का सपना, यह कोई सरकारी सपना नहीं होता है। वो 140 करोड़ देशवासियों का सपना है। ■

प्रधानमंत्री का राज्य सभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर हुई चर्चा का उत्तर

भारत की प्रगति नारी शक्ति से प्रेरित है: प्रधानमंत्री

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने छह फरवरी को राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर हुई चर्चा का जवाब दिया। सदन को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि राष्ट्रपति के अभिभाषण में भारत की उपलब्धियां, दुनिया की भारत से अपेक्षाएं और 'विकसित भारत' के निर्माण में आम आदमी का विश्वास समाहित है। उन्होंने कहा कि अभिभाषण प्रेरक, प्रभावी और भविष्य के कार्यों के लिए मार्गदर्शन प्रदान करने वाला था। श्री मोदी ने राष्ट्रपति के अभिभाषण के लिए उनके प्रति आभार व्यक्त किया

2014 से लगातार सेवा करने का अवसर देने के लिए भारत की जनता का आभार व्यक्त करते हुए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि यह हमारे विकास के मॉडल का प्रमाण है, जिसे जनता ने परखा है, समझा है और समर्थन दिया है। उन्होंने कहा कि 'राष्ट्र प्रथम' वाक्यांश उनके विकास के मॉडल को दर्शाता है और यह सरकार की नीतियों, योजनाओं और कार्यों में स्पष्ट रूप से दिखाई देता है।

श्री मोदी ने कहा, "भारत की प्रगति नारी शक्ति से प्रेरित है।" उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि अगर महिलाओं को अवसर दिए जाएं और वे नीति-निर्माण का हिस्सा बनें, तो इससे देश की प्रगति में और गति आ सकती है। उन्होंने कहा कि यही वजह है कि नई संसद में सरकार का पहला निर्णय नारी शक्ति के सम्मान को समर्पित था।

उन्होंने कहा कि पिछली सरकारों ने डॉ. बाबासाहेब अंबेडकर को कभी भारत रत्न के योग्य नहीं समझा। श्री मोदी ने कहा कि इसके बावजूद देश की जनता ने हमेशा डॉ. अंबेडकर की भावना और आदर्शों का सम्मान किया है। उन्होंने जोर देकर कहा कि समाज के सभी वर्गों से मिले इस सम्मान के कारण ही अब सभी दलों के लोग अनिच्छा से ही सही, लेकिन 'जय भीम' कहने को मजबूर हैं।

गरीबों और वंचितों के कल्याण के लिए अपनी प्रतिबद्धता पर जोर देते हुए उन्होंने कहा कि जिन लोगों की अनदेखी की गई थी, उन्हें अब प्राथमिकता दी जा रही है। श्री मोदी ने इस बात पर जोर देते हुए कहा कि मौजूदा बजट ने चमड़ा और फुटवियर उद्योग जैसे विभिन्न छोटे क्षेत्रों को स्पर्श किया है, जिससे गरीबों और वंचितों को लाभ हुआ है।

आपातकाल: सत्ता की खातिर संविधान को कुचला गया

आपातकाल के दौरान देश के अनुभवों को याद करते हुए, जिस दौरान सत्ता की खातिर संविधान को कुचला गया और उसकी मूल भावना को रौंदा गया, श्री मोदी ने जोर देकर कहा कि देश को यह याद है। उन्होंने इस बात को रेखांकित किया कि आपातकाल के दौरान प्रसिद्ध वरिष्ठ अभिनेता श्री देव आनंद से आपातकाल का सार्वजनिक रूप से समर्थन करने का अनुरोध किया गया था। श्री देव आनंद ने साहस दिखाया और इसका समर्थन करने से इनकार कर दिया, जिसके परिणामस्वरूप दूरदर्शन पर उनकी सभी फिल्मों को प्रतिबंधित कर दिया गया।

श्री मोदी ने कहा, "आज मध्यम वर्ग आत्मविश्वास से भरा हुआ है, जो अभूतपूर्व है और राष्ट्र को बहुत मजबूत बनाता है।" उन्होंने इस बात पर दृढ़ विश्वास व्यक्त किया कि भारतीय मध्यम वर्ग विकसित भारत के सपने को साकार करने के लिए दृढ़ संकल्पित और पूरी तरह तैयार है, जो मजबूती से खड़ा है और एक साथ आगे बढ़ रहा है।

पिछले एक दशक में रक्षा उत्पाद निर्यात में दस गुना वृद्धि

रक्षा विनिर्माण में भारत की उपलब्धियों पर जोर देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले एक दशक में रक्षा उत्पाद निर्यात में दस गुना वृद्धि हुई है, साथ ही सोलर मॉड्यूल विनिर्माण में भी दस गुना वृद्धि हुई है। उन्होंने कहा, "भारत अब दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा इस्पात उत्पादक है", जबकि पिछले एक दशक में मशीनरी और इलेक्ट्रॉनिक निर्यात में तेजी से वृद्धि देखी गई है। श्री मोदी ने यह भी कहा कि खिलौनों का निर्यात तीन गुना से अधिक हो गया है और कृषि रसायन निर्यात में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।

'विकसित भारत' के विजन को आत्मसात करने की सभी भारतीयों की सामूहिक जिम्मेदारी पर जोर देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि यह सिर्फ एक सरकार या एक व्यक्ति का संकल्प नहीं है, बल्कि 140 करोड़ देशवासियों का संकल्प है। ■

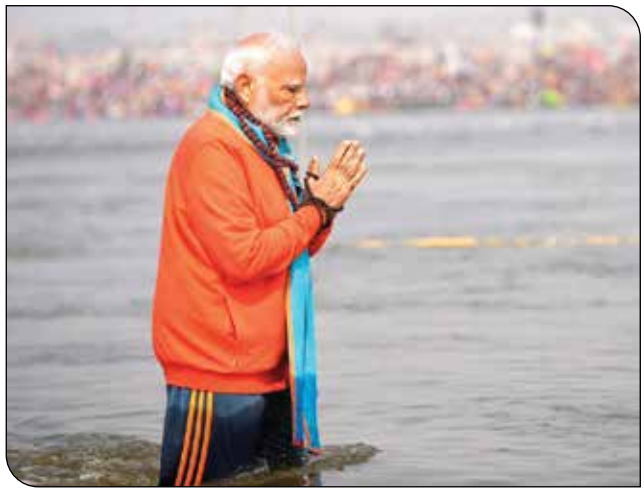

प्रयागराज (उत्तर प्रदेश) में 05 फरवरी, 2025 को महाकुंभ–2025 के दौरान त्रिवेणी संगम में पवित्र स्नान करते प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी

प्रयागराज (उत्तर प्रदेश) में 05 फरवरी, 2025 को महाकुंभ–2025 के दौरान त्रिवेणी संगम में पवित्र स्नान करने के बाद पूजा–अर्चना करते प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी

भुवनेश्वर (ओडिशा) में 28 जनवरी, 2025 को 'उत्कर्ष ओडिशा – मेक इन ओडिशा कॉन्क्लेव 2025' के उद्घाटन समारोह के दौरान प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी

देहरादून (उत्तराखंड) में 28 जनवरी, 2025 को 38वें राष्ट्रीय खेलों के उद्घाटन समारोह में भाग लेते प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी

राजघाट (दिल्ली) में 30 जनवरी, 2025 को महात्मा गांधी की पुण्य तिथि के अवसर पर उन्हें पुष्पांजलि अर्पित करते प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी

नई दिल्ली में 31 जनवरी, 2025 को संसद के बजट सत्र की शुरुआत पर मीडियाकर्मियों से बातचीत करते प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी

कमल संदेश
अब इंटरनेट पर भी उपलब्ध
लॉग इन करें:
www.kamalsandesh.org
राष्ट्रीय विचार की प्रतिनिधि पाक्षिक पत्रिका

@Kamal.Sandesh
@KamalSandesh
kamal.sandesh
KamalSandeshLive

प्रेषण तिथिः (i) 1-2 चालू माह (ii) 16-17 चालू माह
डाकघरः लोदी रोड एचओ., नई दिल्ली "रजिस्टर्ड"
36 पृष्ठ कवर सहित
प्रकाशन तिथिः 18 फरवरी, 2025
आर.एन.आई. DELHIN/2006/16953
डी.एल. (एस)-17/3264/2025-27
Licence to Post without Prepayment
Licence No. U(S)-41/2021-23

दिल्ली में भाजपा की ऐतिहासिक जीत के बाद

पूरे देश में भव्य समारोह

छायाचित्रः अजय कुमार सिंह